रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062026-273590
CG-DL-E-18062026-273590

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 443] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2026/ज्येष्ठ 28, 1948
No. 443] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2026/JYAISTHA 28, 1948

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2026

सा.का.नि. 494(अ).—निम्नलिखित मसौदा नियम, जो केंद्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 4 की उप-धारा (3) और धारा 8 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 56 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (छ) और (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित करती है और सूचित करती है कि राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद उक्त मसौदा नियमों पर विचार किया जाएगा:

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोका रोड, नई दिल्ली- 110001 को भेजे जा सकते हैं:

उक्त मसौदा नियमों के संबंध में उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

अध्याय ।

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों को दूरसंचार (प्रशासनिक प्रक्रिया द्वारा स्पेक्ट्रम समनुदेशन) नियम, 2026 कहा जा सकता है।

(2) ये उस तिथि से लागू होंगे जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

2. परिभाषाएँ– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) है;

(ख) "आशय पत्र" का तात्पर्य नियम 6 के उप-नियम (1) के तहत जारी किया गया पत्र है;

(ग) "पोर्टल" का तात्पर्य नियम 14 में निर्दिष्ट पोर्टल है;

(घ) "स्पेक्ट्रम समनुदेशन" का तात्पर्य नियम 6 के उप-नियम (4) के तहत किसी रेडियो स्टेशन द्वारा स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए जारी की गई अनुमति है; तथा

(ङ) "स्पेक्ट्रम प्रभार" का तात्पर्य रेडियो स्टेशन या रेडियो उपकरण के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क और वो शुल्क है, जो अनुसूची ॥ के संगत अनुलग्नक में विनिर्दिष्ट है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं लेकिन अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियम या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना (नेशनल फ़्रीक्वेंसी अलॉटमेंट प्लान) में परिभाषित हैं, के अर्थ वही होंगे जो उन्हें क्रमशः अधिनियम, उक्त नियमों या उक्त योजना में दिए गए हैं ।

3. कार्यक्षेत्र और प्रयोज्यता--(1) ये नियम अधिनियम की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध प्रविष्टियों के संबंध में प्रशासनिक प्रक्रिया द्वारा स्पेक्ट्रम समनुदेशन के निबंधन और शर्तों को निर्धारित करते हैं।

(2) इन नियमों की अनुसूची-। में ऐसे व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट किया गया है जो अधिनियम की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टियों के संबंध में प्रशासनिक प्रक्रिया द्वारा स्पेक्ट्रम समनुदेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, , ऐसी प्रविष्टियों के लिए विशिष्ट उपयोगों, ऐसी प्रविष्टियों के लिए लागू अनुसूची-॥ के अनुलग्नकों

के साथ-साथ इन नियमों की अनुसूची-II और स्पेक्ट्रम समनुदेशन के निबंधन और शर्तों जो प्रत्येक अनुलग्नक के लिए विशिष्ट हैं, और स्पेक्ट्रम प्रभारों के निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली को विनिर्दिष्ट करते हैं ।

4. पात्रता शर्तें- (1) इन नियमों के तहत स्पेक्ट्रम समनुदेशन के लिए आवेदन करने वाला कोई भी व्यक्ति इन नियमों में और अनुसूची । की प्रासंगिक प्रविष्टि में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करेगा।

(2) यदि स्पेक्ट्रम समनुदेशन के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, ऐसी सरकार द्वारा नामित एजेंसी या कानून के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय नहीं है, तो यह निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करेगा, अर्थात्:-

(क) यदि ऐसा व्यक्ति एक कंपनी है, तो ऐसी कंपनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यदि कोई हो, भारत के मौजूदा कानूनों और नीतियों के अनुरूप होगा; तथा

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति एक कंपनी है, तो ऐसी कंपनी में प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी ऐसे सुरक्षा संबंधी मानदंडों को पूरा करेंगे जिन्हें केंद्रीय सरकार पोर्टल पर विनिर्दिष्ट कर सकती है।

स्पष्टीकरण– इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति–

(क) "लाइसेंस" का तात्पर्य किसी लाइसेंस, पंजीकरण या अनुमति, किसी भी नाम से ज्ञात हो, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के तहत दी गई मंजूरी से है; तथा

(ख) "प्रत्यक्ष विदेशी निवेश" का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के तहत गैर-ऋण लिखतों के संबंध में बनाए गए नियमों में इसे दिया गया है।

(3) उप-नियम (1) से (2) के तहत विनिर्दिष्ट व्यक्ति अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रासंगिक प्रविष्टि के तहत स्पेक्ट्रम समनुदेशन के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा पोर्टल पर यथा विनिर्दिष्ट किसी अन्य मानदंड का भी पालन करेंगे।

अध्याय II

स्पेक्ट्रम समनुदेशन का आवेदन और मंजूरी

5. आवेदन- (1) इन नियमों के अधीन स्पेक्ट्रम समनुदेशन प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रपत्र और रीति से और एक हजार रुपए के अप्रतिदेय आवेदन शुल्क के भुगतान और ऐसी सूचना और दस्तावेजों के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करेगा, जो केंद्रीय सरकार पोर्टल पर विनिर्दिष्ट करे जिसमें शामिल हैं-

(क) स्पेक्ट्रम का विनिर्दिष्ट उपयोग;

(ख) आवेदक द्वारा धारित प्राधिकार या लाइसेंस का प्रकार, यदि लागू हो;

(ग) विधिपूर्ण अपरोधन करने वाले सिस्टम, विधिपूर्ण अपरोधन की निगरानी करने वाली सुविधाओं और केंद्रीय सरकार द्वारा बताई गई किसी भी अन्य अतिरिक्त कार्यात्मक आवश्यकता, यदि लागू हो, के सफल प्रदर्शन का प्रमाण;

(घ) संचालन का भौगोलिक क्षेत्र;

(ङ) ऐसे उपकरणों की तकनीकी डेटा शीट के साथ-साथ आवश्यक रेडियो उपकरणों का अनुमानित प्रकार और मात्रा;

(च) आवृत्ति रेंज और ट्रांसमिशन पैरामीटर, जिसमें बैंडविड्थ, मोड, उत्सर्जन डेज़िग्नेटर, ट्रांसमिट पावर, स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए आवश्यक ईआईआरपी स्तर, और उपयोग किए जाने वाले सैटेलाइट नेटवर्क की जानकारी, इसके कक्षीय मापदंडों और रेडियो संचार सेवा के साथ, यदि लागू हो, शामिल है;

(छ) प्रस्तावित अवधि जिसके लिए स्पेक्ट्रम समनुदेशन की मांग की गई है; तथा

(ज) लागू कानून के तहत अनुमतियां यदि लागू हो तो, उस क्षेत्र के लिए संगत जिसके लिए समनुदेशन मांगा गया है।

बशर्ते कि जहां ऐसा उपकरण है जो दूरसंचार को अवरुद्ध करता है, उसी के संबंध में समनुदेशन की मांग करने वाला व्यक्ति, ऐसे आवेदन के साथ, अधिनियम की धारा 48 के तहत प्राप्त अनुमति प्राप्त करेगा।

(2) यदि उप-नियम (1) के तहत आवेदक एक निश्चित स्थल पर रेडियो उपकरण स्थापित करने का इरादा रखता है, तो वह लागू शुल्क के साथ ऐसे प्रकार और तरीके से लागू मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगा, जैसा कि केंद्रीय सरकार पोर्टल पर विनिर्दिष्ट कर सकती है:

बशर्ते कि यदि केंद्रीय सरकार इस उप-नियम के तहत आवेदन को अस्वीकार कर देती है, तो आवेदक इस तरह की मंजूरी के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकता है, जिसमें रेडियो उपकरण की स्थापना के लिए एक वैकल्पिक साइट दी हो:

बशर्ते यह भी कि अधिनियम की प्रथम अनुसूची की निम्नलिखित प्रविष्टियों के संबंध में स्पेक्ट्रम समनुदेशन के इच्छुक आवेदक स्पेक्ट्रम समनुदेशन प्रदान किए जाने के बाद ऐसी स्वीकृति के लिए आवेदन कर सकते हैं, अर्थात् -

(क) प्रविष्टि 1: राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा;

(ख) प्रविष्टि 2: विधि प्रवर्तन और अपराध निवारण;

(ग) प्रविष्टि 11: पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवाएं;

(घ) प्रविष्टि 12: दूरसंचार सेवाओं के लिए रेडियो बैकहॉल; तथा

(ङ) प्रविष्टि 18: भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)।

स्पष्टीकरण--शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि उप-नियम (2) के तहत पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना एक निश्चित स्थल पर रेडियो उपकरण की स्थापना नहीं की जाएगी।

6. स्पैक्ट्रम समनुदेशन प्रदान करना-(1) केंद्रीय सरकार, ऐसी जांच करने के बाद, जो वह उचित समझे, आवेदक से ऐसी सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगी जिसकी वह मांग कर सकती है और नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन लागू स्वीकृति प्राप्त करने के अध्यधीन और स्पेक्ट्रम की उपलब्धता और संगत सुरक्षा स्वीकृतियों, जहां लागू हो, आशय पत्र जारी करेगी:

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार, जनहित में, नियम 5 के उपनियम (2) के दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट के अलावा अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टियों के संबंध में ऐसी लागू स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व आशय पत्र जारी कर सकती है।

(2) उप-नियम (1) के तहत जारी किए गए आशय पत्र में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होंगे, अर्थात्: -

(क) अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रासंगिक प्रविष्टि और अनुसूची II के लागू अनुलग्नकों के साथ स्पेक्ट्रम समनुदेशन के विशिष्ट उपयोग;

(ख) लागू स्पेक्ट्रम प्रभार और ऐसे प्रभारों के भुगतान के लिए समय-सीमा;

(ग) आवृत्ति रेंज और ट्रांसमिशन पैरामीटर, जिसमें बैंडविड्थ, मोड, उत्सर्जन डेज़िग्नेटर, संचारित शक्ति, स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए आवश्यक ईआईआरपी स्तर, और उपयोग किए जाने वाले सैटेलाइट नेटवर्क की जानकारी, इसके कक्षीय मापदंडों और रेडियो संचार सेवा के साथ, यदि लागू हो तो, शामिल है;

(घ) संचालन का भौगोलिक क्षेत्र;

(ङ) प्रासंगिक रेडियो स्टेशन और ऐसे स्टेशनों का स्थान; तथा

(च) रेडियो उपकरणों का प्रकार और मात्रा।

(3) आशय पत्र का प्राप्तकर्ता, ऐसे पत्र में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर, -

(क) ऐसे पत्र में यथा विनिर्दिष्ट स्पेक्ट्रम प्रभारों के संघटक का भुगतान करेगा, तथा

(ख) संबंधित रेडियो उपकरण की खरीद करेगा।

(4) इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक द्वारा आशय पत्र में विनिदष्ट अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है, केंद्रीय सरकार अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को विनिदष्ट करते हुए पोर्टल के माध्यम से स्पेक्ट्रम समनुदेशन प्रदान करेगी, अर्थात् -

(क) आशय पत्र में विनिर्दिष्ट विवरण; तथा

(ख) स्पेक्ट्रम समनुदेशन की प्रभावी तिथि और अवधि।

बशर्ते कि यदि केंद्रीय सरकार ने रेडियो उपस्करों की संस्थापना के लिए लागू स्वीकृति प्राप्त करने से पहले आशय पत्र जारी किया है तो ऐसी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद स्पेक्ट्रम समनुदेशन प्रदान किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि स्पेक्ट्रम समनुदेशन की अवधि एक कैलेंडर महीने की अवधि से कम है, तो पूरे कैलेंडर महीने के लिए स्पेक्ट्रम प्रभार लागू होगा।

(5) एक समनुदेशिती के पास अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के तहत एक अलग प्राधिकार की अपेक्षा के बिना अपने स्पेक्ट्रम समनुदेशन में निर्दिष्ट रेडियो उपकरण हो सकता है।

(6) केंद्रीय सरकार पोर्टल पर स्पेक्ट्रम समनुदेशन की अधिकतम अवधि और अधिनियम की प्रथम अनुसूची की एक या अधिक प्रविष्टियों के संबंध में इन नियमों के अधीन प्रदान किए जाने वाले स्पेक्ट्रम समनुदेशन की संख्या की सीमा निर्दिष्ट कर सकती है।

7. सामान्य नियम और शर्तें- एक समनुदेशिती निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन करेगा, अर्थात्: -

(क) अनुमत रेडियो उपकरणों की एक अद्यतन सूची बनाना और केवल अधिकृत कर्मियों द्वारा इसकी सुरक्षित हिरासत और संचालन सुनिश्चित करना;

(ख) स्पेक्ट्रम समनुदेशन की अवधि के दौरान नियम 4 में निर्दिष्ट पात्रता शर्तों का पालन करना;

(ग) सुनिश्चित करना कि इसके रेडियो स्टेशन केवल उन विशिष्ट उपयोगों के लिए संचालित होते हैं जिनके लिए स्पेक्ट्रम समनुदेशन प्रदान किया गया है;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करना कि इसका दूरसंचार नेटवर्क अन्य अनुमत दूरसंचार नेटवर्क में हस्तक्षेप नहीं करे;

(ङ) अपने दूरसंचार नेटवर्क को सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क से नहीं जोड़ना, जिसमें सार्वजनिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, सार्वजनिक लैंड मोबाइल नेटवर्क, सैटेलाइट या इंटरनेट द्वारा वैश्विक मोबाइल व्यक्तिगत संचार शामिल है, जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमति न दी जाए;

(च) यह सुनिश्चित करना कि इसका दूरसंचार नेटवर्क मानकों के अनुरूप है, जैसा लागू हो, जिसे केंद्रीय सरकार अधिनियम की धारा 19 के तहत अधिसूचित मानकों सहित निर्दिष्ट कर सकती है;

(छ) केंद्रीय सरकार के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना अपने स्पेक्ट्रम समनुदेशन को सौंपना या हस्तांतरित नहीं करना;

(ज) भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के हित में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करना;

(झ) पोर्टल पर अपने दूरसंचार नेटवर्क को प्रभावित करने वाली अनधिकृत पहुंच, अपरोधन, स्पूफिंग, क्लोनिंग, जैमिंग या अन्य सुरक्षा घटना की किसी भी घटना की रिपोर्ट ऐसे प्रपत्र और तरीके से करना, जो इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है;

(ञ) निम्नलिखित के लिए केंद्रीय सरकार और उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी एजेंसी को सभी आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान करना-

(i) अपने रेडियो उपकरणों के दुरुपयोग, असुरक्षित किए जाने या गैरकानूनी संचालन से संबंधित मामले; तथा

(ii) स्पैक्ट्रम के उपयोग के नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने और निर्धारित स्पेक्ट्रम के हस्तक्षेप-मुक्त उपयोग को सक्षम बनाने के लिए निगरानी और प्रवर्तन; तथा

(ट) इसके रेडियो उपकरणों के नुकसान, चोरी, कब्जे के नुकसान या संदिग्ध दुरुपयोग की किसी भी घटना की सूचना पोर्टल पर ऐसे प्रपत्र और तरीके से देना, जैसा कि इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

8. स्पेक्ट्रम समनुदेशन के निबंधन और शर्तों में संशोधन या परिवर्तन-(1) स्पेक्ट्रम समनुदेशन में विनिर्दिष्ट विवरणों में से रेडियो स्टेशनों के विवरणों, आवृत्ति या किसी अन्य तकनीकी पैरामीटरों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की मांग करने वाला समनुदेशिती पोर्टल पर एक हजार रुपये के गैर-वापसी योग्य शुल्क के साथ ऐसे प्रपत्र में एक आवेदन प्रस्तुत करेगा, जैसा कि केंद्रीय सरकार पोर्टल पर विनिर्दिष्ट कर सकती है।

(2) केंद्रीय सरकार, उप-नियम (1) के अधीन किसी आवेदन की जांच करने और स्पेक्ट्रम की उपलब्धता, जहां लागू हो, संगत सुरक्षा स्वीकृतियों और लागू स्पेक्ट्रम प्रभारों के भुगतान के अध्यधीन ऐसे आवेदन को अनुमोदित कर सकती है और एक अद्यतन स्पेक्ट्रम समनुदेशन प्रदान कर सकती है।

(3) केंद्रीय सरकार, स्वतः संज्ञान लेकर भी समनुदेशन के निबंधन एवं शर्तों को संशोधित और उनमें बदलाव अथवा तकनीकी समायोजन भी कर सकती है, जिसमें आवृत्ति बैंड, शक्ति या उत्सर्जनों के प्रकारों के उपयोग में परिवर्तन करना भी शामिल है, यदि वह संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा करना निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए समीचीन है -

(क) राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना के प्रावधान;

(ख) उपस्करों के संबंध में कुशल स्पेक्ट्रम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बेहतर तकनीकी मानकों को लागू करने की आवश्यकता;

(ग) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रेडियो हस्तक्षेप शमन आवश्यकता; तथा

(घ) स्पेक्ट्रम के री-फार्मिंग, सामंजस्य या इष्टतम उपयोग के संबंध में कोई भी नियम, जो केंद्रीय सरकार निर्धारित कर सकती है।

(4) केंद्रीय सरकार, उप-नियम (3) के अधीन किसी संशोधन या भिन्नता के अनुसरण में, संबंधित समनुदेशिती को एक अद्यतन स्पेक्ट्रम समनुदेशन प्रदान करेगी।

(5) समनुदेशिती पोर्टल पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर इस नियम के तहत किसी भी संशोधन या भिन्नता को लागू करेगा।

(6) इस नियम के तहत स्पेक्ट्रम समनुदेशन में कोई भी संशोधन या भिन्नता मूल रूप से समनुदेशिती को जारी किए गए स्पेक्ट्रम समनुदेशन में निर्दिष्ट अवधि को प्रभावित नहीं करेगी।

अध्याय III

नवीनीकरण और समर्पण

9. नवीनीकरण- (1) प्रविष्टि 18, अर्थात्, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), के अलावा अधिनियम की पहली अनुसूची की किसी भी प्रविष्टि के संबंध में स्पेक्ट्रम समनुदेशन धारण करने वाला एक समनुदेशिती, स्पेक्ट्रम समनुदेशन के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, इसकी समाप्ति की तारीख से कम से कम एक महीने पहले, इस तरह के प्रपत्र और तरीके से और ऐसे स्पेक्ट्रम प्रभारों के साथ जैसा कि केंद्रीय सरकार पोर्टल पर निर्दिष्ट कर सकती है।

(2) किसी समनुदेशिती से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, केंद्रीय सरकार उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् आवेदन की अनुमति दे सकती है, यदि वह संतुष्ट हो जाती है कि ऐसी अवधि के भीतर ऐसा आवेदन न करने का पर्याप्त कारण था, बशर्ते कि ऐसे विलंब शुल्क का भुगतान किया जाता है जैसा कि केंद्रीय सरकार ऐसे अनुरोध के उत्तर में विनिर्दिष्ट कर सकती है।

(3) अधिनियम की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 19 के अधीन परीक्षण अथवा प्रायोगिक के संबंध में जारी किए गए स्पेक्ट्रम समनुदेशन के नवीनीकरण के लिए उप-नियम (1) के अधीन कोई भी आवेदन, ऐसे परीक्षण या प्रयोग के परिणाम और ऐसे नवीनीकरण की मांग करने के कारणों को प्रमाणित करने वाले सहायक दस्तावेजों के साथ संलग्न किया जाएगा।

(4) केंद्रीय सरकार, अपने विवेक से, उप-नियम (1) या (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, इन नियमों और ऐसे नवीनीकरण के समय लागू कानून और नीति के अनुपालन के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्णीत की जाने वाली अवधि के लिए स्पेक्ट्रम समनुदेशन का नवीनीकरण कर सकती है।

(5) अधिनियम की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 18 अर्थात्, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), के संबंध में स्पेक्ट्रम समनुदेशन नवीनीकरण के लिए पात्र नहीं होगा और संबंधित समनुदेशिती स्पेक्ट्रम समनुदेशन प्राप्त करने के लिए नियम 5 के तहत एक नया आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

10. स्पेक्ट्रम का समर्पण–(1) स्पेक्ट्रम समर्पण करने का इच्छुक कोई समनुदेशिती समर्पण की प्रस्तावित तारीख से कम से कम तीस दिन पहले ऐसे प्रपत्र और रीति से जैसा कि केंद्रीय सरकार पोर्टल पर विनिर्दिष्ट करे, , स्पेक्ट्रम प्रभारों के भुगतान के प्रमाण या आवेदन की तारीख तक उसके द्वारा संदेय किसी अन्य लागू देय के प्रमाण और ऐसी अन्य जानकारी ऐसे प्रपत्र में जो केंद्रीय सरकार पोर्टल पर निर्दिष्ट कर सकती है, के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(2) केंद्रीय सरकार उप-नियम (1) के तहत एक आवेदन को अनुमोदित या अस्वीकार कर सकती है, और यदि अनुमोदित किया जाता है, तो समर्पण की प्रभावी तारीख इस तरह के आवेदन की प्राप्ति की तारीख से इकतीसवें दिन होगी, या समर्पण की प्रस्तावित तारीख, जो भी बाद में हो।

(3) स्पेक्ट्रम के समर्पण के बाद, यदि केंद्रीय सरकार यह निर्धारित करती है कि समनुदेशिती द्वारा देय सभी देय राशियों के निपटान के बाद कोई शेष राशि है, तो वह या तो समनुदेशिती के अन्य सक्रिय समनुदेशन के लिए लंबित ऐसी राशियों को समायोजित कर सकती है या समनुदेशिती को ऐसी राशि वापस कर सकती है।

(4) इस नियम के तहत अपने स्पेक्ट्रम को समर्पण करने वाले प्रत्येक समनुदेशिती, केंद्रीय सरकार को देय सभी राशियों का भुगतान करेगा जिसमें उप-नियम (2) में यथा निर्दिष्ट समर्पण की प्रभावी तारीख तक देय स्पेक्ट्रम प्रभार भी शामिल है।

(5) अधिनियम की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 18 के संबंध में स्पेक्ट्रम का समर्पण दूरसंचार (नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम समनुदेशन) नियम, 2026 के अनुसार किया जाएगा।

11. रेडियो उपकरणों का निपटान- (1) नीचे दी गई सारणी 1 में निर्दिष्ट किसी भी घटना के घटित होने पर, संबंधित समनुदेशिती नीचे सारणी । में निर्दिष्ट अवधि के अनुसार स्पेक्ट्रम समनुदेशन में निर्दिष्ट रेडियो उपकरणों का निपटान करेगा-

सारणी ।

क्रम संख्या	**निपटान से संबंधित घटना**	**निपटान के लिए सीमा**
1.	नवीकरण न होने के कारण स्पेक्ट्रम समनुदेशन की समाप्ति।	ऐसी समाप्ति के तीन महीने के भीतर।
2.	नियम 10 के तहत किए गए समर्पण के लिए किए गए आवेदन को केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति।	इस तरह के समर्पण की प्रभावी तिथि से दो महीने के भीतर।
3.	नियम 7 के तहत केंद्रीय सरकार के एक आदेश के अनुसार समनुदेशन का निरसन।	इस तरह के आदेश की तारीख से दो महीने के भीतर।

(2) संबंधित समनुदेशिती उप-नियम (1) के अधीन किसी भी विधि का प्रयोग करते हुए, जैसा कि केंद्रीय सरकार पोर्टल पर विनिर्दिष्ट करे, का निपटान करेगा और ऐसे निपटान का प्रमाण देने वाला दस्तावेज ऐसे प्रपत्र और रीति से प्रस्तुत करेगा, जैसा कि केंद्रीय सरकार उस पर विनिर्दिष्ट करे।

अध्याय IV

विविध

12. केन्द्रीय सरकार की शक्तियाँ–(1) केंद्रीय सरकार पोर्टल पर भारत के राज्यक्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, नियंत्रण रेखा, भारत की वास्तविक नियंत्रण रेखा या किसी अन्य क्षेत्र के निकट आने वाले प्रतिबंधित क्षेत्रों में समनुदेशिती द्वारा स्पेक्ट्रम के उपयोग पर प्रतिबंध विनिर्दिष्ट कर सकती है, जैसा कि केंद्रीय सरकार पोर्टल पर विनिर्दिष्ट कर सकती है।

(2) केंद्रीय सरकार, इन नियमों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे आदेश, निदेश या दिशानिर्देश जारी कर सकती है जो अधिनियम या इन नियमों से असंगत न हों, जो प्रत्येक समनुदेशिती पर लागू निबंधन और शर्तों का गठन करेंगे।

(3) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इन नियमों की अनुसूचियों में संशोधन कर सकती है।

13. उल्लंघन- (1) एक समनुदेशिती द्वारा इन नियमों के तहत नियमों और शर्तों का उल्लंघन अधिनियम की धारा 32 में निर्दिष्ट उल्लंघन माना जाएगा।

(2) केंद्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्राप्त सिफारिशों पर विधिवत विचार करने के पश्चात् और समनुदेशिती को सुनने का अवसर देने के पश्चात् अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन स्पेक्ट्रम समनुदेशन के निलंबन, निरसन या कटौती का आदेश जारी कर सकती है।

(3) उप-नियम (2) के तहत प्रत्येक आदेश केंद्रीय सरकार द्वारा पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, और ऐसे आदेश के प्रकाशन की तारीख से तुरंत प्रभावी होगा:

बशर्ते कि समनुदेशन, प्राधिकार या लाइसेंस का निलंबन समनुदेशन की अवधि के विस्तार के लिए एक कारण या आधार नहीं होगा।

(4) समनुदेशिती किसी समनुदेशन के संबंध में भुगतान किए गए शुल्क या किसी अन्य शुल्क की वापसी का हकदार नहीं होगा जो निलंबन, निरसन, कटौती, संशोधन या भिन्नता का विषय है।

14. डिजिटल कार्यान्वयन- केंद्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 53 के अनुसरण में, इन नियमों के डिजिटल कार्यान्वयन, जिसमें इन नियमों के तहत निर्दिष्ट किए जाने वाले किसी भी प्रपत्र, तरीके, आदेश, निर्देश या दिशानिर्देश का प्रकाशन शामिल है, के लिए एक या एक से अधिक पोर्टलों को अधिसूचित कर सकती है, ।

अनुसूची ।

(नियम 3(2) और 4 देखें)

स्पेक्ट्रम समनुदेशन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र व्यक्ति	**विशिष्ट उपयोग**	**स्पेक्ट्रम प्रभारों के निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली सहित विशिष्ट निबंधन और शर्तों पर लागू अनुलग्नक**
1. राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा		
अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 1 के प्रयोजन के लिए केंद्रीय	(क) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यू एचएफ बैंड में लैंड मोबाइल सेवा, जिसमें 375 KHZ तक की बैंडविड्थ है;	(क) अनुलग्नक-II: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/

सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा नामित कोई एजेंसी।	(ख) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यू एचएफ बैंड में समुद्री मोबाइल सेवा; (ग) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यू एचएफ बैंड में वैमानिकी सेवा; (घ) रेडियोनेविगेशन और रेडियोलोकेशन सेवाओं के लिए रडार; (ङ) मल्टीप्लेक्स मल्टी-चैनल वाली फिक्स्ड और मोबाइल सेवाएं; तथा (च) सैटेलाइट आधारित सेवाएं।	यूएचएफ बैंड में लैंड मोबाइल सेवा, जिसमें 375 KHZ तक की बैंडविड्थ है; (ख) अनुलग्नक-III: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/ यूएचएफ बैंड में समुद्री मोबाइल सेवा; (ग) अनुलग्नक-IV: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/ यूएचएफ बैंड में वैमानिकी सेवा; (घ) अनुलग्नक-V: रेडियोनेविगेशन और रेडियोलोकेशन सेवाओं के लिए रडार; (ङ) अनुलग्नक-VI: मल्टीप्लेक्स मल्टी-चैनलों वाली फिक्स्ड और मोबाइल सेवाएं; (च) अनुलग्नक-VII: सैटेलाइट आधारित सेवा; तथा (छ) अनुलग्नक-XIII: स्पेक्ट्रम प्रभारों के विलंबित भुगतान के लिए विलंब शुल्क।
2. विधि प्रवर्तन और अपराध रोकथाम		
(क) अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 2 के प्रयोजनार्थ केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या ऐसी सरकार द्वारा नामित कोई एजेंसी; तथा (ख) यदि खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम समनुदेशन चाहता है,	(क) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यू एचएफ बैंड में लैंड मोबाइल सेवा, जिसमें 375 KHZ तक की बैंडविड्थ है; (ख) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यू एचएफ बैंड में समुद्री मोबाइल सेवा; (ग) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यू एचएफ बैंड में वैमानिकी सेवा; (घ) रेडियोनेविगेशन और रेडियोलोकेशन सेवाओं के लिए रडार; (ङ) मल्टीप्लेक्स मल्टी-चैनल वाली फिक्स्ड और मोबाइल सेवाएं; तथा (च) सैटेलाइट आधारित सेवाएं।	(क) अनुलग्नक-II: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/ यूएचएफ बैंड में लैंड मोबाइल सेवा, जिसमें 375 KHZ तक की बैंडविड्थ है; (ख) अनुलग्नक-III: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/ यूएचएफ बैंड में समुद्री मोबाइल सेवा; (ग) अनुलग्नक-IV: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यू एचएफ बैंड में वैमानिकी सेवा; (घ) अनुलग्नक-V: रेडियोनेविगेशन और रेडियोलोकेशन सेवाओं के लिए रडार;

तो ऐसे व्यक्ति के पास दूरसंचार (कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 के तहत कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्राधिकार भी होगा।		(ङ) अनुलग्नक-VI: मल्टीप्लेक्स मल्टी-चैनलों वाली फिक्स्ड और मोबाइल सेवाएं; (च) अनुलग्नक-VII: सैटेलाइट आधारित सेवाएं; तथा (छ) अनुलग्नक-XIII: स्पेक्ट्रम प्रभारों के विलंबित भुगतान के लिए विलंब शुल्क।
3. लोक प्रसारण सेवाएं		
संबंधित प्राधिकार या लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति, जैसा कि केंद्रीय सरकार पोर्टल पर निर्दिष्ट करे।	स्थलीय प्रसारण सेवा	(क) अनुलग्नक-I: स्थलीय प्रसारण सेवा; तथा (ख) अनुलग्नक-XIII: स्पेक्ट्रम प्रभारों के विलंबित भुगतान के लिए विलंब शुल्क।
4. आपदा प्रबंधन, जीवन और संपत्ति की रक्षा		
(क) अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 4 के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या ऐसी सरकार द्वारा नामित कोई एजेंसी; (ख) संसद द्वारा या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय, जिसे अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 4 के प्रयोजन के लिए कार्यकलाप	(क) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ बैंड में लैंड मोबाइल सेवा, जिसमें 375 KHZ तक की बैंडविड्थ है; (ख) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ बैंड में समुद्री मोबाइल सेवा; (ग) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ बैंड में वैमानिकी सेवा; (घ) रेडियोनेविगेशन और रेडियोलोकेशन सेवाओं के लिए रडार; (ङ) मल्टीप्लेक्स मल्टी-चैनल वाली फिक्स्ड और मोबाइल सेवाएं; तथा (च) सैटेलाइट आधारित सेवाएं।	(क) अनुलग्नक-II: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ बैंड में लैंड मोबाइल सेवा, जिसमें 375 KHZ तक की बैंडविड्थ है; (ख) अनुलग्नक-III: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ बैंड में समुद्री मोबाइल सेवा; (ग) अनुलग्नक-IV: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ बैंड में वैमानिकी सेवा (घ) अनुलग्नक-V: रेडियोनेविगेशन और रेडियोलोकेशन सेवाओं के लिए रडार; (ङ) अनुलग्नक-VI: मल्टीप्लेक्स मल्टी-चैनलों वाली फिक्स्ड और मोबाइल सेवाएं; (च) अनुलग्नक-VII: सैटेलाइट आधारित सेवाएं; तथा

को करने की शक्तियां प्राप्त हैं; (ग) खंड (क) और (ख) के तहत निर्दिष्ट के इतर कोई भी व्यक्ति, जो नियम 4 के उप-नियम (2) के तहत निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है; तथा (घ) यदि खंड (क) से (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम समनुदेशन चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति के पास दूरसंचार (कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 के तहत एक कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्राधिकार भी होगा।		(छ) अनुलग्नक-XIII: स्पेक्ट्रम प्रभारों के विलंबित भुगतान के लिए विलंब शुल्क।
लागू विधि के अनुसार, एक्सेस स्पेक्ट्रम के लिए एक्सेस सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ स्पेक्ट्रम समनुदेशन प्रदान करने के लिए प्राधिकार रखने वाला कोई भी व्यक्ति, इस अनुसूची की प्रविष्टि 4 के	पोर्टल पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार उपयोग किया जाएगा।	अनुलग्नक-XI: एक्सेस स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क।

संबंध में तीन महीने से अनधिक की अवधि के लिए स्पेक्ट्रम समनुदेशन की मांग कर सकता है।		
5. वैज्ञानिक अनुसंधान, संसाधन विकास और खोज का संवर्धन		
(क) अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 5 के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या ऐसी सरकार द्वारा नामित कोई एजेंसी; (ख) संसद द्वारा या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के तहत स्थापित कोई सांविधिक निकाय, जिसे अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 5 के प्रयोजन के लिए कार्यकलाप को करने की शक्तियां प्राप्त हैं; तथा (ग) खंड (क) और (ख) के तहत निर्दिष्ट के इतर कोई भी व्यक्ति, जो नियम 4 के उप-नियम (2) के तहत निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है।	(क) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/ यूएचएफ बैंड में लैंड मोबाइल सेवा, जिसमें 375 KHZ तक की बैंडविड्थ है; (ख) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/ यूएचएफ बैंड में समुद्री मोबाइल सेवा; (ग) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/ यूएचएफ बैंड में वैमानिकी सेवा; (घ) रेडियोनेविगेशन और रेडियोलोकेशन सेवाओं के लिए रडार; (ङ) मल्टीप्लेक्स मल्टी-चैनल वाली फिक्स्ड और मोबाइल सेवाएं; तथा (च) सैटेलाइट आधारित सेवाएं।	(क) अनुलग्नक-II: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/ यूएचएफ बैंड में लैंड मोबाइल सेवा, जिसमें 375 KHZ तक की बैंडविड्थ है; (ख) अनुलग्नक-III: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/ यूएचएफ बैंड में समुद्री मोबाइल सेवा (ग) अनुलग्नक-IV: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/ यूएचएफ बैंड में वैमानिकी सेवा; (घ) अनुलग्नक-V: रेडियोनेविगेशन और रेडियोलोकेशन सेवाओं के लिए रडार; (ङ) अनुलग्नक-VI: मल्टीप्लेक्स मल्टी-चैनलों वाली फिक्स्ड और मोबाइल सेवाएं; (च) अनुलग्नक-VII: सैटेलाइट आधारित सेवाएं; तथा (छ) अनुलग्नक-XIII: स्पेक्ट्रम प्रभारों के विलंबित भुगतान के लिए विलंब शुल्क।

6. सड़कों, रेल मार्गों, मैट्रो, क्षेत्रीय रेल, अन्तरदेशीय जलमार्गों, विमानपत्तनों, पाइप लाइनों, पोत परिवहन और अन्य यातायात प्रणालियों की सुरक्षा और प्रचालन।		
(क) अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 6 के प्रयोजनार्थ केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या ऐसी सरकार द्वारा नामित कोई एजेंसी; (ख) संसद द्वारा या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन स्थापित कोई सांविधिक निकाय, जिसे अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 6 के प्रयोजन के लिए कार्यकलाप करने की शक्तियां प्राप्त हों; (ग) खंड (क) और (ख) के तहत निर्दिष्ट के इतर कोई भी व्यक्ति, जो नियम 4 के उप-नियम (2) के तहत निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है; (घ) यदि खंड (क) से (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति, कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम	(क) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ बैंड में लैंड मोबाइल सेवा, जिसमें 375 KHZ तक की बैंडविड्थ है; (ख) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ बैंड में समुद्री मोबाइल सेवा; (ग) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ बैंड में वैमानिकी सेवा; (घ) रेडियोनेविगेशन और रेडियोलोकेशन सेवाओं के लिए रडार; (ङ) मल्टीप्लेक्स मल्टी-चैनल वाली फिक्स्ड और मोबाइल सेवाएं; (च) सैटेलाइट आधारित सेवाएं; तथा (छ) मेट्रो और क्षेत्रीय रेल प्रणालियों की सुरक्षा और संचालन के संबंध में सेवाएं।	(क) अनुलग्नक-II: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ बैंड में लैंड मोबाइल सेवा, जिसमें 375 KHZ तक की बैंडविड्थ है; (ख) अनुलग्नक-III: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ बैंड में समुद्री मोबाइल सेवा; (ग) अनुलग्नक-IV: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ बैंड में वैमानिकी सेवा; (घ) अनुलग्नक-V: रेडियोनेविगेशन और रेडियोलोकेशन सेवाओं के लिए रडार; (ङ) अनुलग्नक-VI: मल्टीप्लेक्स मल्टी-चैनलों वाली फिक्स्ड और मोबाइल सेवाएं; (च) अनुलग्नक-VII: सैटेलाइट आधारित सेवाएं; (छ) अनुलग्नक-XI: एक्सेस स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क; तथा (ज) अनुलग्नक-XIII: स्पेक्ट्रम प्रभारों के विलंबित भुगतान के लिए विलंब शुल्क।

समनुदेशन चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति के पास दूरसंचार (कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 के तहत एक कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्राधिकार भी होगा; तथा (ङ) खंड (क) से (ग) के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति उस क्षेत्र के लिए प्रासंगिक विधि के तहत प्रासंगिक अनुमतियां भी रखेंगे जिसके लिए समनुदेशन मांगा गया है।		
7. प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीवन का संरक्षण		
(क) अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 7 के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या ऐसी सरकार द्वारा नामित कोई एजेंसी; (ख) संसद द्वारा या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के तहत स्थापित कोई	(क) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/ यूएचएफ बैंड में लैंड मोबाइल सेवा, जिसमें 375 KHZ तक की बैंडविड्थ है; (ख) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/ यूएचएफ बैंड में समुद्री मोबाइल सेवा; (ग) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/ यूएचएफ बैंड में वैमानिकी सेवा; (घ) रेडियोनेविगेशन और रेडियोलोकेशन सेवाओं के लिए रडार; (ङ) मल्टीप्लेक्स मल्टी-चैनल वाली फिक्स्ड और मोबाइल सेवाएं; तथा (च) सैटेलाइट आधारित सेवाएं।	(क) अनुलग्नक-II: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/ यूएचएफ बैंड में लैंड मोबाइल सेवा, जिसमें 375 KHZ तक की बैंडविड्थ है; (ख) अनुलग्नक-III: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/ यूएचएफ बैंड में समुद्री मोबाइल सेवा; (ग) अनुलग्नक-IV: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/ यूएचएफ बैंड में वैमानिकी सेवा; (घ) अनुलग्नक-V: रेडियोनेविगेशन और रेडियोलोकेशन सेवाओं के लिए रडार;

सांविधिक निकाय, जिसे अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 7 के प्रयोजन के लिए कार्यकलापों को करने की शक्तियां प्राप्त हैं; तथा (ग) खंड (क) और (ख) के तहत निर्दिष्ट के इतर कोई भी व्यक्ति, जो नियम 4 के उप-नियम (2) के तहत निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है।		(ङ) अनुलग्नक-VI: मल्टीप्लेक्स मल्टी-चैनलों वाली फिक्स्ड और मोबाइल सेवाएं; (च) अनुलग्नक-VII: सैटेलाइट आधारित सेवाएं; तथा (छ) अनुलग्नक-XIII: स्पेक्ट्रम प्रभारों के विलंबित भुगतान के लिए विलंब शुल्क।
8. मौसम विभाग और मौसम पूर्वानुमान		
(क) अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 8 के प्रयोजनार्थ केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या ऐसी सरकार द्वारा नामित कोई एजेंसी; (ख) संसद द्वारा या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के तहत स्थापित कोई सांविधिक निकाय, जिसे अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 8 के प्रयोजन	(क) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ बैंड में लैंड मोबाइल सेवा, जिसमें 375 KHZ तक की बैंडविड्थ है; (ख) रेडियोनेविगेशन और रेडियोलोकेशन सेवाओं के लिए रडार; (ग) मल्टीप्लेक्स मल्टी-चैनल वाली फिक्स्ड और मोबाइल सेवाएं; तथा (घ) सैटेलाइट आधारित सेवाएं।	(क) अनुलग्नक-II: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ बैंड में लैंड मोबाइल सेवा, जिसमें 375 KHZ तक की बैंडविड्थ है; (ख) अनुलग्नक-V: रेडियोनेविगेशन और रेडियोलोकेशन सेवाओं के लिए रडार; (ग) अनुलग्नक-VI: मल्टीप्लेक्स मल्टी-चैनलों वाली फिक्स्ड और मोबाइल सेवाएं; (घ) अनुलग्नक-VII: सैटेलाइट आधारित सेवाएं; तथा (ङ) अनुलग्नक-XIII: स्पेक्ट्रम प्रभारों के विलंबित भुगतान के लिए विलंब शुल्क।

के लिए कार्यकलाप को शुरू करने की शक्ति है; तथा (ग) खंड (क) और (ख) के तहत निर्दिष्ट के अलावा कोई भी व्यक्ति, जो नियम 4 के उप-नियम (2) के तहत निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है।		
9. अव्यवसायी स्टेशनों, नौ-परिवहन, दूरमिति और अन्य समान उपयोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त समर्पित बैंड		
(क) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 9 के उद्देश्य से ऐसी सरकार द्वारा नामित कोई एजेंसी; (ख) संसद द्वारा या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय, जिसे अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 9 के प्रयोजन के लिए गतिविधियों को करने की शक्तियां हैं; तथा (ग) खंड (क) और (ख) के तहत निर्दिष्ट के	(क) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/ यूएचएफ बैंड में लैंड मोबाइल सेवा, जिसमें 375 KHZ तक की बैंडविड्थ है; (ख) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/ यूएचएफ बैंड में मेरीटाइम मोबाइल सेवा; (ग) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/ यूएचएफ बैंड में वैमानिकी सेवा; (घ) रेडियोनेविगेशन और रेडियोलोकेशन सेवाओं के लिए रडार; (ङ) मल्टीप्लेक्स मल्टी-चैनल वाली फिक्स्ड और मोबाइल सेवाएं; तथा (च) सैटेलाइट आधारित सेवाएं।	(क) अनुलग्नक-II: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/ यूएचएफ बैंड में लैंड मोबाइल सेवा, जिसमें 375 KHZ तक की बैंडविड्थ है; (ख) अनुलग्नक-III: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/ यूएचएफ बैंड में मेरीटाइम मोबाइल सेवा; (ग) अनुलग्नक-IV: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/ यूएचएफ बैंड में वैमानिकी सेवा; (घ) अनुलग्नक-V: रेडियोनेविगेशन और रेडियोलोकेशन सेवाओं के लिए रडार; (ङ) अनुलग्नक-VI: मल्टीप्लेक्स मल्टी-चैनलों वाली फिक्स्ड और मोबाइल सेवाएं; (च) अनुलग्नक-VII: सैटेलाइट आधारित सेवाएं; तथा (छ) अनुलग्नक-XIII: स्पेक्ट्रम शुल्क के भुगतान में देरी के लिए विलंब शुल्क

अलावा कोई भी व्यक्ति, जो नियम 4 के उप-नियम (2) के तहत निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है।		
10. खानें, पत्तनों और तेल की खोज की सुरक्षा और प्रचालनों तथा ऐसे अन्य क्रियाकलापों के लिए, जहां स्पैक्ट्रम का उपयोग प्राथमिक रूप से सुरक्षा और प्रचालनों का समर्थन करने के लिए है, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, या उनके अस्तित्वों या अन्य प्राधिकृत अस्तित्वों द्वारा उपयोग		
(क) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 10 के प्रयोजन के लिए ऐसी सरकार द्वारा नामित कोई एजेंसी; (ख) संसद द्वारा या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन स्थापित एक सांविधिक निकाय, जिसे अधिनियम की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 10 के प्रयोजन के लिए कार्यकलाप करने की शक्तियां हों; (ग) खंड (क) और (ख) के तहत निर्दिष्ट के अलावा कोई भी व्यक्ति, जो नियम 4 के उप-नियम (2) के	(क) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/ यूएचएफ बैंड में लैंड मोबाइल सेवा, जिसमें 375 KHZ तक की बैंडविड्थ है; (ख) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/ यूएचएफ बैंड में मेरीटाइम मोबाइल सेवा; (ग) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/ यूएचएफ बैंड में वैमानिकी सेवा; (घ) रेडियोनेविगेशन और रेडियोलोकेशन सेवाओं के लिए रडार; (ङ) मल्टीप्लेक्स मल्टी-चैनल वाली फिक्स्ड और मोबाइल सेवाएं; तथा (च) सैटेलाइट आधारित सेवाएं।	(क) अनुलग्नक-II: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/ यूएचएफ बैंड में लैंड मोबाइल सेवा, जिसमें 375 KHZ तक की बैंडविड्थ है; (ख) अनुलग्नक-III: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/ यूएचएफ बैंड में मेरीटाइम मोबाइल सेवा; (ग) अनुलग्नक-IV: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/ यूएचएफ बैंड में वैमानिकी सेवा; (घ) अनुलग्नक-V: रेडियोनेविगेशन और रेडियोलोकेशन सेवाओं के लिए रडार; (ङ) अनुलग्नक-VI: मल्टीप्लेक्स मल्टी-चैनलों वाली फिक्स्ड और मोबाइल सेवाएं; (च) अनुलग्नक-VII: सैटेलाइट आधारित सेवाएं; तथा (छ) अनुलग्नक-XIII: स्पेक्ट्रम प्रभारों के विलंबित भुगतान के लिए विलंब शुल्क।

तहत निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है; (घ) यदि खंड (क) से (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम समनुदेशन की मांग करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास दूरसंचार (कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 के तहत एक कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्राधिकार भी होगा; तथा (ङ) खंड (क) से (ग) के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति उस क्षेत्र के लिए प्रासंगिक कानून के तहत प्रासंगिक अनुमतियां भी रखेंगे जिसके लिए समनुदेशन मांगा गया है।		
11. पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवाएं		
(क) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या अधिनियम की पहली अनुसूची की	पीएमआरटी सेवा	(क) अनुलग्नक-VIII: पीएमआरटी सेवा; तथा

प्रविष्टि 11 के प्रयोजन के लिए ऐसी सरकार द्वारा नामित कोई एजेंसी; (ख) संसद द्वारा या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय, जिसे अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 11 के प्रयोजन के लिए गतिविधियों को करने की शक्तियां हैं; तथा (ग) केंद्रीय सरकार के रूप में संबंधित प्राधिकार या लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति, जैसा कि पोर्टल पर निर्दिष्ट कर सकता है।		(ख) अनुलग्नक-XIII: स्पेक्ट्रम प्रभारों के विलंबित भुगतान के लिए विलंब शुल्क।
12. दूरसंचार सेवाओं के लिए रेडियो बैकहॉल		
पोर्टल पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट आवृत्तियों की श्रेणी में स्पेक्ट्रम रखने वाली निम्नलिखित संस्थाएं: (क) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या अधिनियम की	रेडियो बैकहॉल	अनुलग्नक-X: रेडियो बैकहॉल।

पहली अनुसूची की प्रविष्टि 12 के प्रयोजन के लिए ऐसी सरकार द्वारा नामित कोई एजेंसी; (ख) संसद द्वारा या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के तहत स्थापित कोई सांविधिक निकाय, जिसे अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 12 के प्रयोजन के लिए गतिविधियों को करने की शक्तियां हैं; तथा (ग) केंद्रीय सरकार के रूप में संबंधित प्राधिकार या लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति, जैसा कि पोर्टल पर निर्दिष्ट कर सकता है।		
13. सामुदायिक रेडियो स्टेशन		
केंद्रीय सरकार के रूप में संबंधित प्राधिकार या लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति, जैसा कि पोर्टल पर निर्दिष्ट कर सकता है।	स्थलीय प्रसारण सेवा	(क) अनुलग्नक-I: स्थलीय प्रसारण सेवा; तथा (ख) अनुलग्नक-XIII: स्पेक्ट्रम प्रभारों के विलंबित भुगतान के लिए विलंब शुल्क।

14. इन-फ्लाइट और समुद्रीय सहबद्धधता		
(क) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 14 के प्रयोजन के लिए ऐसी सरकार द्वारा नामित कोई एजेंसी; (ख) संसद द्वारा या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय, जिसे अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 14 के प्रयोजन के लिए गतिविधियों को करने की शक्तियां हैं; तथा (ग) केंद्रीय सरकार के रूप में संबंधित प्राधिकार या लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति, जैसा कि पोर्टल पर निर्दिष्ट कर सकता है।	इन-फ्लाइट और समुद्रीय सहबद्धधता	कोई स्पेक्ट्रम शुल्क लागू नहीं होगा।
15. अंतरिक्ष अनुसंधान और अनुप्रयोग, प्रस्थान यान प्रचालन और सैटेलाइट नियंत्रण के लिए आधार स्टेशन		
(क) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या अधिनियम की	सैटेलाइट आधारित सेवाएं	(क) अनुलग्नक-VII: सैटेलाइट आधारित सेवाएं; तथा

पहली अनुसूची की प्रविष्टि 15 के प्रयोजन के लिए ऐसी सरकार द्वारा नामित कोई एजेंसी; (ख) संसद द्वारा या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय, जिसे अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 15 के प्रयोजन के लिए गतिविधियों को करने की शक्तियां हैं; तथा (ग) खंड (क) और (ख) के तहत निर्दिष्ट के अलावा कोई भी व्यक्ति, जो नियम 4 के उप-नियम (2) के तहत निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है।		(ख) अनुलग्नक-XIII: स्पेक्ट्रम प्रभारों के विलंबित भुगतान के लिए विलंब शुल्क।
16. नीचे सूचीबद्ध कुछ सैटेलाइट-आधारित सेवाएँ:		
<u>16(क). टेलीपोर्ट</u>		
केंद्रीय सरकार के रूप में संबंधित प्राधिकार या लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति, जैसा कि पोर्टल पर निर्दिष्ट कर सकता है।	सैटेलाइट आधारित सेवाएं	(क) अनुलग्नक-VII: सैटेलाइट आधारित सेवाएं; तथा (ख) अनुलग्नक-XIII: स्पेक्ट्रम प्रभारों के विलंबित भुगतान के लिए विलंब शुल्क।

16(ख). टेलीविजन चैनल		
केंद्रीय सरकार के रूप में संबंधित प्राधिकार या लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति, जैसा कि पोर्टल पर निर्दिष्ट कर सकता है।	सैटेलाइट आधारित सेवाएं	(क) अनुलग्नक-VII: सैटेलाइट आधारित सेवाएं; तथा (ख) अनुलग्नक-XIII: स्पेक्ट्रम प्रभारों के विलंबित भुगतान के लिए विलंब शुल्क।
16(ग). डायरेक्ट टू होम		
केंद्रीय सरकार के रूप में संबंधित प्राधिकार या लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति, जैसा कि पोर्टल पर निर्दिष्ट कर सकता है।	सैटेलाइट आधारित सेवाएं	(क) अनुलग्नक-VII: सैटेलाइट आधारित सेवाएं; तथा (ख) अनुलग्नक-XIII: स्पेक्ट्रम प्रभारों के विलंबित भुगतान के लिए विलंब शुल्क।
16(घ). हैडएंड इन द स्काई		
केंद्रीय सरकार के रूप में संबंधित प्राधिकार या लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति, जैसा कि पोर्टल पर निर्दिष्ट कर सकता है।	सैटेलाइट आधारित सेवाएं	(क) अनुलग्नक-VII: सैटेलाइट आधारित सेवाएं; तथा (ख) अनुलग्नक-XIII: स्पेक्ट्रम प्रभारों के विलंबित भुगतान के लिए विलंब शुल्क।
16(ङ). डिजिटल सैटेलाइट समाचार एकत्रीकरण		
केंद्रीय सरकार के रूप में संबंधित प्राधिकार या लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति, जैसा कि पोर्टल पर निर्दिष्ट कर सकता है।	सैटेलाइट आधारित सेवाएं	(क) अनुलग्नक-VII: सैटेलाइट आधारित सेवाएं; तथा (ख) अनुलग्नक-XIII: स्पेक्ट्रम प्रभारों के विलंबित भुगतान के लिए विलंब शुल्क।
16 (च) (1). वैरी स्माल एपर्चर टर्मिनल (कैप्टिव)		
(क) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या ऐसी सरकार द्वारा नामित कोई भी एजेंसी वैरी स्माल	भू-स्थिर कक्षा का उपयोग करते हुए सैटेलाइट आधारित सेवाएं	(क) अनुलग्नक-VII: सैटेलाइट आधारित सेवाएं; तथा (ख) अनुलग्नक-XIII: स्पेक्ट्रम प्रभारों के विलंबित भुगतान के लिए विलंब शुल्क।

एपर्चर टर्मिनल (कैप्टिव) के संबंध में अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 16 के प्रयोजन के लिए; (ख) संसद द्वारा या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अधीन स्थापित एक सांविधिक निकाय, जिसे वैरी स्माल ऐपर्चर टर्मिनल (कैप्टिव) के संबंध में अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 16 के प्रयोजन के लिए गतिविधियों को करने की शक्तियां हैं; तथा (ग) केंद्रीय सरकार के रूप में संबंधित प्राधिकार या लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति, पोर्टल पर निर्दिष्ट कर सकता है।		
16 <u>(च)(2). वैरी स्माल एपर्चर टर्मिनल (वाणिज्यिक)</u>		
(क) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या ऐसी सरकार द्वारा नामित कोई भी	भू-स्थिर कक्षा का उपयोग करते हुए सैटेलाइट आधारित वाणिज्यिक संचार सेवाएं	अनुलग्नक-IX: सैटेलाइट आधारित वाणिज्यिक संचार सेवाएं।

एजेंसी वैरी स्माल एपर्चर टर्मिनल (वाणिज्यिक) के संबंध में अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 16 के प्रयोजन के लिए; केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत, (ख) संसद द्वारा या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय, जिसके पास वैरी स्माल एपर्चर टर्मिनल (वाणिज्यिक) के संबंध में अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 16 के प्रयोजन के लिए गतिविधियों को शुरू करने की शक्तियां हैं; तथा (ग) केंद्रीय सरकार के रूप में संबंधित प्राधिकार या लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति, जैसा कि पोर्टल पर निर्दिष्ट कर सकता है।		

16 (छ). राष्ट्रीय लंबी दूरी		
(क) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या राष्ट्रीय लंबी दूरी के संबंध में अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 16 के प्रयोजन के लिए ऐसी सरकार द्वारा नामित कोई एजेंसी; (ख) संसद द्वारा या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय, जिसे राष्ट्रीय लंबी दूरी के संबंध में अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 16 के प्रयोजन के लिए गतिविधियों को शुरू करने की शक्तियां हैं; तथा (ग) केंद्रीय सरकार के रूप में संबंधित प्राधिकार या लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति, पोर्टल पर निर्दिष्ट कर सकता है।	सैटेलाइट आधारित सेवाएं	(क) अनुलग्नक-VII: सैटेलाइट आधारित सेवाएं; तथा (ख) अनुलग्नक-XIII: स्पेक्ट्रम प्रभारों के विलंबित भुगतान के लिए विलंब शुल्क।

16 (ज). अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी		
(क) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या ऐसी सरकार द्वारा नामित कोई भी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के संबंध में अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 16 के प्रयोजन के लिए; (ख) संसद द्वारा या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अधीन स्थापित एक सांविधिक निकाय, जिसे अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के संबंध में अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 16 के प्रयोजन के लिए गतिविधियों को शुरू करने की शक्तियां हों; तथा (ग) केंद्रीय सरकार के रूप में संबंधित प्राधिकार या लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर निर्दिष्ट कर सकता है।	सैटेलाइट आधारित सेवाएं	(क) अनुलग्नक-VII: उपग्रह आधारित सेवाएं; तथा (ख) अनुलग्नक-XIII: स्पेक्ट्रम प्रभारों के विलंबित भुगतान के लिए विलंब शुल्क।

16 (झ). अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट मोबाइल सैटेलाइट सेवा बैंड		
भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) एसयूआई जेनेरिस श्रेणी के अंतर्गत	भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा एसयूआई जेनेरिस श्रेणी के अंतर्गत ग्लोबल सैटेलाइट फोन सेवा (जीएसपीएस)।	अनुलग्नक-IX: सैटेलाइट आधारित वाणिज्यिक संचार सेवाएं।
17. दूरसंचार सेवाओं के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या उनकी प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा उपयोग		
(क) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 17 के प्रयोजन के लिए ऐसी सरकार द्वारा नामित कोई एजेंसी; (ख) यदि खंड (ए) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम समनुदेशन चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति के पास दूरसंचार (कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 के तहत कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्राधिकार भी होगा।	(क) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ बैंड में लैंड मोबाइल सेवा, जिसमें 375 KHZ तक की बैंडविड्थ है; (ख) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ बैंड में समुद्री मोबाइल सेवा; (ग) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ बैंड में वैमानिकी सेवा; (घ) रेडियोनेविगेशन और रेडियोलोकेशन सेवाओं के लिए रडार; (ङ) मल्टीप्लेक्स मल्टी-चैनल वाली फिक्स्ड और मोबाइल सेवाएं; तथा (च) सैटेलाइट आधारित सेवाएं।	(क) अनुलग्नक-II: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ बैंड में लैंड मोबाइल सेवा, जिसमें 375 KHZ तक की बैंडविड्थ है; (ख) अनुलग्नक-III: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ बैंड में समुद्री मोबाइल सेवा; (ग) अनुलग्नक-IV: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ बैंड में वैमानिकी सेवा; (घ) अनुलग्नक-V: रेडियोनेविगेशन और रेडियोलोकेशन सेवाओं के लिए रडार; (ङ) अनुलग्नक-VI: मल्टीप्लेक्स मल्टी-चैनलों वाली फिक्स्ड और मोबाइल सेवाएं; (च) अनुलग्नक-VII: सैटेलाइट आधारित सेवाएं; तथा (छ) अनुलग्नक-XIII: स्पेक्ट्रम प्रभार के भुगतान में देरी के लिए विलंब शुल्क
18. भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) एन्ड महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)		
(क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल); और		अनुलग्नक-XI: एक्सेस स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम प्रभार।

(ख) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल),जो प्रासंगिक प्राधिकार या लाइसेंस धारण करेगा, जैसा कि केंद्रीय सरकार पोर्टल पर विनिर्दिष्ट कर सकती है।		
19. नई प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन को समर्थ बनाने के लिए परीक्षण जांच, परिप्रयोग, प्रदर्शन, जिसके अंतर्गत एक या अधिक विनियामक सैंडबाक्स का सृजन भी है		
(क) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 19 के प्रयोजन के लिए ऐसी सरकार द्वारा नामित कोई एजेंसी; (ख) संसद द्वारा या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय, जिसे अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 19 के प्रयोजन के लिए गतिविधियों को करने की शक्तियां हैं; तथा	नई प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन को समर्थ बनाने के लिए परीक्षण जांच, परिप्रयोग, प्रदर्शन, जिसके अंतर्गत एक या अधिक विनियामक सैंडबाक्स का सृजन भी है ।	अनुलग्नक-XII: नई प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन को समर्थ बनाने के लिए परीक्षण जांच, परिप्रयोग, प्रदर्शन, जिसके अंतर्गत एक या अधिक विनियामक सैंडबाक्स का सृजन भी है।

(ग) केंद्रीय सरकार के रूप में संबंधित प्राधिकार या लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर निर्दिष्ट कर सकता है।		

अनुसूची II

(नियम 3(2) और 6(2) देखें)

अनुलग्नक-I: स्थलीय प्रसारण सेवा

1. यह अनुलग्नक अनुसूची-I की प्रविष्टियों 3 और 13 के संबंध में स्थलीय प्रसारण सेवा (सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं और सामुदायिक रेडियो प्रसारण सेवाओं सहित) के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन पर लागू होगा।

2. इस अनुलग्नक में निम्नलिखित शामिल हैं:

   (क) वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क को विनिदष्ट करने वाली सारणी-क-1 और क-2; तथा

   (ख) रेडियो स्टेशन और रेडियो उपकरण शुल्क निर्दिष्ट करने वाली सारणी ख।

सारणी क1: वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क

प्रसारण का प्रकार	**एंटीना को दी गई शक्ति**	**प्रति रेडियो स्टेशन वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क (रुपये में)**
प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) के तहत स्थापित प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) द्वारा सार्वजनिक प्रसारण सेवाएं	**ध्वनि:**	
	लो पावर एफएम (100 डब्ल्यू तक)	30,000
	मध्यम शक्ति एफएम (0.1 किलोवाट-1 किलोवाट)	60,000
	हाई पावर एफएम (1कि.वा. -3 कि.वा.)	1,25,000
	एएम/मेगावाट प्रसारण	50,000
	टेलीविजन:	
	लो पावर टीवी (1 कि.वा. तक)	वीएचएफ: 1,20,000 यूएचएफ: 3,60,000
	हाई पावर टीवी (1 कि.वा. से ऊपर)	वीएचएफ: 1,20,000 यूएचएफ: 3,50,000
प्रसार भारती के इतर किसी अन्य संस्था द्वारा सार्वजनिक प्रसारण सेवाएं	एफएम स्टेशन	3,37,500

सामुदायिक रेडियो प्रसारण	कम शक्ति एफएम (50 डब्ल्यू तक)	22,500 सामुदायिक रेडियो प्रसारण के लिए स्टैंडबाय रेडियो स्टेशन के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी और कोई शुल्क देय नहीं है।

सारणी क2: कम शक्ति वाले इनडोर रेडियो उपकरणों के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क

स्पेक्ट्रम शुल्क (रु. में)	5,000 प्रति रेडियो उपकरण, उपकरण के जीवनकाल के लिए।

सारणी ख: रेडियो स्टेशन / रेडियो उपकरण शुल्क

क्र.सं.	**रेडियो स्टेशन/रेडियो उपकरण का प्रकार (स्टैंडबाय सेट सहित)**	**रेडियो स्टेशन/रेडियो उपस्कर शुल्क (रुपये में)**
1.	प्रसारण ट्रांसमीटर स्टेशन	500 प्रति रेडियो स्टेशन प्रति वर्ष
2.	कम शक्ति वाले इनडोर रेडियो उपकरण: *बशर्ते कि* ऐसे उपकरणों का उपयोग सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों या आउट्डोर में स्टेडियमों में आयोजित कार्यक्रमों सहित बाहरी कार्यक्रमों के लिए नहीं किया जाएगा।	250 प्रति रेडियो उपकरण, उपकरण के जीवनकाल के लिए।
3.	हॉट स्टैंडबाय उपकरण	शून्य

अनुलग्नक-II: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ बैंड में लैंड मोबाइल सेवा, जिसमें 375 KHZ तक की बैंडविड्थ है।

1. यह अनुलग्नक अनुसूची I की प्रविष्टि 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 17 के संबंध में 375 KHZ तक बैंडविड्थ वाले एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ बैंड में लैंड मोबाइल सेवा के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन पर लागू होगा।

2. इस अनुलग्नक में निम्नलिखित शामिल हैं:

   (क) फिक्स्ड-साइट नेटवर्क के लिए वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क निर्दिष्ट करने वाली सारणी क2 और क3 के साथ पठित सारणी क1, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

      (i) छोटे क्षेत्र के अनुप्रयोग जैसे औद्योगिक इकाइयाँ, कारखानों और नगर पालिकाएँ; तथा

      (ii) एक या एक से अधिक बेस स्टेशन, मोबाइल स्टेशन, या उसके किसी भी संयोजन, जहां एक जिले का क्षेत्र चार बेस या रिपीटर स्टेशनों द्वारा कवर किए जाने के लिए पर्याप्त छोटा है;

   (ख) यूएचएफ शॉर्ट रेंज रेडियो (यूएसआर) के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क निर्दिष्ट करने वाली सारणी ख;

   (ग) लैंड मोबाइल स्टेशनों के लिए वीएचएफ/यूएचएफ बैंड में क्षेत्र-आधारित संचालन के लिए वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क निर्दिष्ट करने वाली सारणी ग, जिसमें फिक्स्ड-साइट श्रेणी से परे कवरेज वाला दूरसंचार नेटवर्क शामिल है, जहां क्षेत्र उपयोगकर्ता वे हैं जो संचालन के बड़े क्षेत्र में काम करते हैं जैसे:

      (i) अखिल भारतीय उपयोगकर्ता, जैसे: भारतीय रेलवे, रक्षा, केंद्रीय अर्धसैनिक बल (सीपीएमएफ), तेल विपणन कंपनियां और हवाई अड्डा प्राधिकरण;

      (ii) राज्य-व्यापी उपयोगकर्ता, जैसे: राज्य पुलिस संगठन, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य वन विभाग, बिजली बोर्ड और जल संसाधन विभाग;

      (iii) जिले-व्यापी उपयोगकर्ता, जैसे: सार्वजनिक परिवहन, जिला प्राधिकरण; तथा

      (iv) बेस स्टेशन, मोबाइल स्टेशन, और उनके किसी भी संयोजन;

   (घ) एलएफ/एमएफ/एचएफ बैंड प्रति 3 KHZ बैंडविड्थ में लैंड मोबाइल सेवा के लिए वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क विनिदष्ट करने वाली सारणी घ; और

   (ङ) अनुलग्नक II पर लागू वार्षिक रेडियो स्टेशन शुल्क निर्दिष्ट करने वाली सारणी ङ।

(च) दूरसंचार को अवरुद्ध करने वाले उपकरणों पर लागू रेडियो उपकरण शुल्क निर्दिष्ट करने वाली सारणी च।

3. इस अनुलग्नक के तहत स्पेक्ट्रम के आवंटन के संबंध में रेडियो आवृत्ति के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:

(क) नियम 6 के उपनियम (1) के तहत जारी किए गए आशय पत्र और नियम 6 के नियम उप-नियम (4) के तहत जारी स्पेक्ट्रम समनुदेशन पत्र, 10 सिम्प्लेक्स आवृत्ति या 2 डुप्लेक्स आवृत्ति की अधिकतम सीमा तक सीमित ऑपरेशन की आवृत्ति रेंज को निर्दिष्ट करेगा।

(ख) एक समनुदेशिती बाद में, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर, पोर्टल पर निर्दिष्ट फॉर्म में एक आवेदन जमा करके, उसी के औचित्य के साथ, अतिरिक्त आवृत्तियों के लिए अनुरोध कर सकता है।

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त आवृत्तियों के किसी भी अनुदान को स्पेक्ट्रम समनुदेशन पत्र के संशोधन के रूप में दर्ज किया जाएगा।

4. इस अनुलग्नक के तहत स्पेक्ट्रम के आवंटन के संबंध में स्पेक्ट्रम शुल्क लगाने के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

(क) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ बैंड के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क चैनल बैंडविड्थ के लिए लगाया जाएगा, न कि आक्यपाइड (occupied) बैंडविड्थ के लिए।

(ख) सारणी ए1 में यथा निर्दिष्ट स्पेक्ट्रम शुल्क निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(i) सारणी A1 में निर्दिष्ट शुल्क का आधा हिस्सा 6.25 kHz या उससे कम की बैंडविड्थ के लिए लागू होगा, और 12.5 kHz से अधिक बैंडविड्थ के लिए, स्पेक्ट्रम शुल्क 12.5 kHz के गुणकों में लिया जाएगा, और किसी भी भिन्नात्मक बैंडविड्थ को 12.5 kHz के अगले गुणक तक पूर्णांकित किया जाएगा।

(ii) दो स्थानों यानी शहरों के विभिन्न वर्गों में जनसंख्या श्रेणियों में फैले दूरसंचार नेटवर्क के मामले में, उच्च जनसंख्या श्रेणी का शुल्क लागू होगा।

(iii) आवृत्ति समनुदेशन के लिए वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क जो समुद्र (अपतटीय), उप-सतह उपयोग, जैसे सुरंग-रेडियो में हैं, संबंधित बैंड और जनसंख्या श्रेणी में न्यूनतम चार्जिंग दर पर लिया जाएगा।

(iv) यदि रेडियो उपकरण के एंटीना का उपयोग घर के अंदर या भूमिगत किया जाता है या डाउन-फायर, लीकी फीडर या रेडिएटिंग केबल प्रकार है, तो यह संबंधित बैंड और जनसंख्या श्रेणी की श्रेणी 1 के भीतर आएगा।

(v) सारणी क1 में वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क पहले 10 सिम्प्लेक्स आवृत्तियों या 2 डुप्लेक्स आवृत्तियों के लिए लागू होगा।

(vi) आवृत्तियों की मात्रा से इतर, अगली 5 सिम्प्लेक्स आवृत्तियों या 2 डुप्लेक्स आवृत्तियों के लिए 30% अधिक का वृद्धिशील अतिरिक्त शुल्क और 15 सिम्प्लेक्स या 4 डुप्लेक्स आवृत्तियों से अधिक आवृत्तियों की संख्या पर 50% अधिक शुल्क लागू होगा।

(vii) दूरसंचार को अवरुद्ध करने वाले उपकरणों के लिए कोई स्पेक्ट्रम शुल्क लागू नहीं होगा।

<u>फिक्स्ड-साइट नेटवर्क के लिए वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क के लिए सारणी क1, क2, क3</u>

सारणी क1: वीएचएफ/यूएचएफ बैंड प्रति 12.5 kHz बैंडविड्थ में फिक्स्ड-साइट नेटवर्क के लिए वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क

बैंड श्रेणी[1]	**अत्यधिक लोकप्रिय बैंड (एचपीबी) के लिए वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क (रुपये में)**			**मीडियम पॉपुलर बैंड (एमपीबी) के लिए वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क (रुपये में)**			**कम लोकप्रिय बैंड (एलपीबी) के लिए वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क (रुपये में)**
कवरेज श्रेणी[2]	1	2	3	1	2	3	1,2 या 3
जनसंख्या श्रेणी* क+	15,000	45,000	75,000	12,000	36,000	45,000	3,000
जनसंख्या श्रेणी* क	10,000	25,000	40,000	8,000	24,000	36,000	
जनसंख्या श्रेणी* ख	7,500	15,000	25,000	5,000	12,000	20,000	
जनसंख्या श्रेणी* ग	5,000	10,000	15,000	3,750	7,000	15,000	
अन्य सभी	3,000	5,000	8,000	3,000	4,000	5,000	

[1]सारणी - क2 देखें।

[2]सारणी - क3 देखें।

*जनसंख्या श्रेणियां केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

सारणी क2: अत्यधिक/मीडियम/कम लोकप्रिय बैंड

बैंड श्रेणियां	बैंड	फ़्रिक्वेंसी रेंज (MHz)
अत्यधिक लोकप्रिय बैंड (एचपीबी)	वीएचएफ	137-174
	यूएचएफ-आई	410-430
	यूएचएफ-II	430-470
मीडियम लोकप्रिय बैंड (एमपीबी)	यूएचएफ-III	380 -400 सीएमआरटीएस के लिए 800 MHz (आईएमटी बैंड को छोड़कर)
कम लोकप्रिय बैंड (एलपीबी)	उपरोक्त के अलावा कोई अन्य बैंड	

सारणी क3: कवरेज श्रेणी

कवरेज श्रेणियां	वाट (पी) में प्रभावी विकिरणित शक्ति (ईआरपी) का संयोजन, और भू स्तर से ऊपर एंटीना की ऊंचाई (एएच) मीटर में - बेस स्टेशन के लिए	संभावित प्रचालन क्षेत्र - त्रिज्या (R) किमी में
श्रेणी 1	पी ≤**5**डब्ल्यू और एएच ≤**10** मीटर	0 < आर ≤**3**
श्रेणी 2	पी ≤**5**डब्ल्यू और 10 मीटर < एएच ≤**30** मीटर	3 < आर ≤15
	पी> 5डब्ल्यू और एएच ≤**10** मीटर	
श्रेणी 3	पी> 5डब्ल्यू और एएच > 10 मीटर	15 < आर ≤**30**
	पी ≤**5**डब्ल्यू और एएच > 30 मीटर	

सारणी ख: यूएचएफ शॉर्ट रेंज रेडियो (यूएसआर) के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क

स्पेक्ट्रम शुल्क (रु. में)	15,000 प्रति आवृत्ति स्पॉट, 5 वर्ष के लिए

सारणी ग: लैंड मोबाइल स्टेशनों के लिए वीएचएफ/यूएचएफ बैंड में क्षेत्र-आधारित संचालन के लिए वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क

कार्य-क्षेत्र	अत्यधिक लोकप्रिय बैंड के लिए वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क (रुपये में)	मीडियम लोकप्रिय बैंड के लिए वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क (रुपये में)	कम लोकप्रिय बैंड के लिए वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क (रुपये में)
पैन इंडिया	50,00,000	37,50,000	25,00,000

राज्यव्यापी **-श्रेणी क**[1]	5,00,000	3,75,000	2,50,000
राज्यव्यापी **-**श्रेणी **ख**[2]	3,00,000	2,25,000	1,50,000
जिलाव्यापी	5 x फिक्स्ड-साइट कवरेज श्रेणी-3 (**सारणी** क 3 के अनुसार)	5 x फिक्स्ड-साइट कवरेज श्रेणी-3 (**सारणी** क 3 के अनुसार)	5 x फिक्स्ड-साइट कवरेज श्रेणी-3 (**सारणी** क 3 के अनुसार)

[1]राज्यव्यापी श्रेणी-क: दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा।

[2]राज्यव्यापी श्रेणी -ख: उत्तराखंड, सिक्किम, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम और संघ-राज्य क्षेत्र ।

सारणी घ: एलएफ/एमएफ/एचएफ बैंड प्रति 3 kHz बैंडविड्थ में लैंड मोबाइल सेवा के लिए वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क

आवृत्ति बैंड	**वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क (रु. प्रति वर्ष में) प्रति स्पॉट (सेटों की संख्या पर ध्यान दिए बिना)**
एचएफ (3 - 30 MHz)	1,00,000
एमएफ (300 kHz - 3 MHz)	50,000
एलएफ (9 kHz - 300 kHz)	50,000

सारणी ङ: अनुलग्नक II के लिए लागू वार्षिक रेडियो स्टेशन शुल्क

क्र.सं.	**रेडियो स्टेशन का प्रकार**	**वार्षिक रेडियो स्टेशन शुल्क (रु. में)**
1.	बेस/फिक्स्ड रेडियो स्टेशन	500 प्रति रेडियो स्टेशन
2.	वाहन/हैंडहेल्ड मोबाइल रेडियो स्टेशन	250 प्रति रेडियो स्टेशन

सारणी च: दूरसंचार को अवरुद्ध करने वाले उपकरणों के लिए रेडियो उपकरण शुल्क

क्र.सं.	**उपकरण का प्रकार**	**जीवन भर के लिए रेडियो उपकरण शुल्क (रुपये में)**
1.	**फिक्स्ड**	500 प्रति उपकरण
2.	मोबाइल (वाहन/हैंडहेल्ड/परीक्षा केंद्र जैसे स्थान)	250 प्रति उपकरण

अनुलग्नक-III: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ बैंड में समुद्री मोबाइल सेवा

1. यह अनुलग्नक अनुसूची I की प्रविष्टियों 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 और 17 के संबंध में एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ बैंड (एनएफएपी में परिभाषित बंदरगाह संचालन सेवा और जहाज संचलन सेवा सहित) में समुद्री मोबाइल सेवा के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन पर लागू होगा।

2. इस अनुलग्नक में शामिल हैं:

   (क) <u>सारणी क</u> वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क को विनिर्दिष्ट करती है; और

   (ख) <u>सारणी ख</u> वार्षिक रेडियो स्टेशन शुल्क विनिर्दिष्ट करती है।

3. इस अनुलग्नक के तहत स्पेक्ट्रम का आवंटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

   (क) सार्वजनिक संस्था के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को आवृत्ति समनुदेशन गैर-अनन्य आधार पर किया जाएगा।

   (ख) सार्वजनिक संस्थाएं जो बंदरगाहों और खोज व बचाव (एसएआर) में लगी हुई हैं, उन्हें अनन्य आधार पर अनुरोधित संख्या में आवृत्तियों को प्रदान किया जाएगा।

   (ग) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ बैंड के लिए वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क और जो 30 MHz से अधिक है, चैनल बैंडविड्थ के लिए लगाया जाएगा, न कि आक्यपाइड (occupied) बैंडविड्थ के लिए।

   (घ) वीएचएफ समुद्री मोबाइल बैंड में संचारण फ्रीक्वेन्सियों आईटीयू-आर के रेडियो विनियमन के परिशिष्ट 18 के अनुसार होगी, जैसा कि समय-समय पर अद्यतन किया जा सकता है।

   (ङ) आवृत्ति बैंड वीएचएफ (एआईएस/एटीओएन[2]) में, दो फ्रीक्वेन्सियों का न्यूनतम समनुदेशन होगा।

4. स्पेक्ट्रम प्रभार केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित फ्रीक्वेन्सियों के लिए लागू नहीं होंगे जैसा कि निम्नलिखित के संबंध में निर्धारित किया गया है: (क) संकट तात्कालिकता और सुरक्षा संचार, और (ख) अंतर-जहाज सुरक्षा संचार।

सारणी क: वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क

निम्नलिखित सारणी में, निम्नलिखित के संबंध में वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क निर्दिष्ट किया गया है:

1. यूएचएफ बैंड प्रति 12.5 kHz बैंडविड्थ है, और, 6.25 kHz या उससे कम की आवृत्ति बैंडविड्थ के लिए, निर्दिष्ट शुल्क का आधा हिस्सा लागू होगा;

2. 12.5 kHz से अधिक बैंडविड्थ वाले वीएचएफ/यूएचएफ बैंड को 12.5 kHz के गुणकों में चार्ज किया जाएगा, और किसी भी भिन्नात्मक बैंडविड्थ को 12.5 kHz के अगले गुणक तक पूर्णांकित किया जाएगा; तथा

3. एलएफ/एमएफ/एचएफ बैंड प्रति 3 kHz बैंडविड्थ है।

आवृत्ति बैंड	**वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क (रुपये में) (रेडियो उपकरणों के सेटों की संख्या के बावजूद)**
वीएचएफ (एआईएस[1] को छोड़कर)/यूएचएफ	20,000
वीएचएफ (एआईएस/एटीओएन[2])	20,000, दो आवृत्तियों के लिए
एचएफ (3 - 30 MHz)	1,00,000
एमएफ (300 kHz - 3 MHz)	50,000
एलएफ (9 kHz - 300 kHz)	50,000

[1] *एआईएस: स्वचालित पहचान प्रणाली*

[2] *एटीओएन: नेविगेशन में सहायता के लिए एआईएस (भौतिक/आभासी/सिंथेटिक)*

सारणी ख : वार्षिक रेडियो स्टेशन शुल्क

क्र.सं.	**रेडियो स्टेशन का प्रकार**	**वार्षिक रेडियो स्टेशन शुल्क (रुपये में)**
1.	तट स्टेशन	500 प्रति रेडियो स्टेशन
2.	वाहन/हैंडहेल्ड रेडियो स्टेशन	250 प्रति रेडियो स्टेशन
3.	फिशिंग ट्रॉलर	500 प्रति ट्रॉलर
4.	जहाज स्टेशन	5000 प्रति जहाज

अनुलग्नक-IV: एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ बैंड में एयरोनोटीकल सर्विस

1. यह अनुलग्नक अनुसूची । की प्रविष्टियों 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 और 17 के संबंध में एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ बैंड में एयरोनोटीकल सर्विस के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन पर लागू होगा।

2. एयरोनोटीकल सर्विस में एयरोनोटीकल मोबाइल (रूट) सर्विस, एयरोनोटीकल मोबाइल (ऑफ-रूट) सर्विस और एयरोनोटीकल रेडियो नेविगेशन सर्विस शामिल होगी, जैसा कि एनएफएपी में परिभाषित है।

3. इस अनुलग्नक में निम्नलिखित शामिल हैं:

   (क) सारणी क में वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क विनिर्दिष्ट हैं; और

   (ख) सारणी ख में रेडियो स्टेशन शुल्क विनिर्दिष्ट हैं।

4. इस अनुलग्नक के प्रयोजनार्थ-

   (क) "एरोनॉटिकल मोबाइल सर्विस" या "एएमएस" का अर्थ है एयरोनोटीकल स्टेशनों और विमान स्टेशनों के बीच या विमान स्टेशनों के बीच एक मोबाइल सर्विस, जिसमें बचाव यान स्टेशन भाग ले सकते हैं, इमरजेंसी स्थिति-संकेतक रेडियोबीकन स्टेशन भी विनिर्दिष्ट संकट और इमरजेंसी आवृत्ति पर इस सर्विस में भाग ले सकते हैं।

   (ख) "एरोनॉटिकल रेडियोनेविगेशन सर्विस" या "एआरएनएस" का अर्थ है विमानों के लाभ और सुरक्षित प्रचालन के लिए अभिप्रेत रेडियोनेविगेशन सर्विस।

5. इस अनुलग्नक के अंतर्गत स्पेक्ट्रम का आवंटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

   (क) इस अनुलग्नक के संबंध में आवृत्ति आवंटन अनन्य आधार पर किया जाएगा।

   (ख) एलएफ/एमएफ/एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ बैंड के लिए वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क, जो 30 MHz से अधिक है, चैनल बैंडविड्थ के लिए लगाया जाएगा, न कि उपयोग की गई बैंडविड्थ के लिए।

   (ग) आपातकालीन स्थिति एवं सुरक्षा संचार के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित आवृत्ति पर स्पेक्ट्रम प्रभार लागू नहीं होगा।

सारणी क: वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क

नीचे दी गई सारणी में निम्नलिखित के संबंध में विनिर्दिष्ट वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क दिए गए हैं:

1. वीएचएफ/यूएचएफ बैंड 12.5 kHz बैंडविड्थ के अनुसार है, और 6.25 kHz या उससे कम बैंडविड्थ के लिए, विनिर्दिष्ट शुल्क का आधा लागू होगा;

2. 12.5 kHz से अधिक बैंडविड्थ वाले वीएचएफ/यूएचएफ बैंडों के लिए शुल्क 12.5 kHz के गुणकों में लिया जाएगा, और किसी भी भिन्नात्मक बैंडविड्थ को 12.5 kHz के अगले गुणक तक पूर्णांकित किया जाएगा; और

3. एलएफ/एमएफ/एचएफ बैंड प्रति 3 kHz बैंडविड्थ के हैं।

आवृत्ति बैंड	**प्रति स्थान वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क (रुपये में) (रेडियो उपकरण सेटों की संख्या के बावजूद)**
वीएचएफ/यूएचएफ (एआरएनएस/एएमएस)*	2,00,000 (टावर और अप्रोच के लिए) 75,000 (ग्राउंड के लिए)
एचएफ (3-30 MHz)	1,00,000
एमएफ (300 kHz-3 MHz)	50,000
एलएफ (9 kHz-300 kHz) (रेडियो बीकन)	50,000

***एआरएनएस**: एरोनॉटिकल रेडियोनेविगेशन सर्विस जैसे आईएलएस (इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम), वीओआर (वीएचएफ ओम्नी-डायरेक्शनल रेंज), एनडीबी (नॉन-डायरेक्शनल बीकन)

***एएमएस**: एयरोनोटीकल मोबाइल सर्विस (रूट/ऑफ-रूट)

सारणी ख: वार्षिक रेडियो स्टेशन शुल्क

क्र.सं.	**रेडियो स्टेशन का प्रकार**	**रेडियो स्टेशन का वार्षिक शुल्क (रुपये में)**
1.	फिक्सड रेडियो स्टेशन	प्रति रेडियो स्टेशन 500
2.	व्हीकल/हैंडहेल्ड मोबाइल रेडियो स्टेशन	प्रति रेडियो स्टेशन 250
3.	एयरक्राफ्ट स्टेशन	प्रति एयरक्राफ्ट 5000

अनुलग्नक-V: रेडियोनेविगेशन और रेडियो लोकेशन सर्विस के लिए रडार

1. यह अनुलग्नक अनुसूची । की प्रविष्टियों 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 17 के संबंध में रेडियोनेविगेशन और रेडियो लोकेशन सर्विस के लिए रडार के स्पेक्ट्रम के आवंटन पर लागू होगा।

2. इस अनुलग्नक में निम्नलिखित शामिल हैं:

   (क) सारणी क को सारणी ग के साथ पढ़ा जाए जिसमें एआरएनएस (बैंडविड्थ >375 kHz के लिए) और विंड प्रोफ़ाइलर रडार सहित उच्च शक्ति रडार (ईआईआरपी ≥10 वाट) के लिए वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क विनिर्दिष्ट किया गया है।

   (ख) सारणी ख को सारणी ग के साथ पढ़ा जाए जिसमें कम शक्ति वाले रडारों (ईआईआरपी <10 वाट) के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क विनिर्दिष्ट किया गया है; और

   (ग) सारणी घ में रेडियो स्टेशन शुल्क विनिर्दिष्ट किया गया है।

3. इस अनुलग्नक के अंतर्गत स्पेक्ट्रम के आवंटन पर निम्नलिखित शर्त लागू होगी:

   (क) सारणी क और सारणी ख के लिए आवृत्ति बैंड आवश्यक बैंडविड्थ के आधार पर सारणी ग में विनिर्दिष्ट तरीके से निर्धारित किया जाएगा; और

   (ख) सारणी क और सारणी ख के अंतर्गत स्पेक्ट्रम शुल्क की गणना सारणी ग में विनिर्दिष्ट आवश्यक बैंडविड्थ (20 डीबी बैंडविड्थ) के आधार पर की जाएगी और यह कवरेज दूरी से स्वतंत्र होगी।

सारणी क: वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क

रेडियो स्टेशन का प्रकार	आवृत्ति बैंड	प्रति 100 kHz वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क (रुपये में)
उच्च शक्ति रडार (ईआईआरपी>=10वाट) जिसमें एआरएनएस A (बैंडविड्थ >375 के लिए) शामिल है।	2690 MHz तक	12,000
	2690-5000 MHz	
	5000-8500 MHz	3,000
	8500 -14500 MHz	1,200
	14500 MHz से अधिक	
विंड प्रोफ़ाइलर रडार	2690 MHz तक	4,000
	2690 -5000 MHz	
	5000-8500 MHz	1,000
	8500 -14500 MHz	400
	14500 MHz से अधिक	

सारणी ख: कम शक्ति वाले रडारों (ईआईआरपी<10 वाट) के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क

रेडियो स्टेशन का प्रकार	**आवृत्ति बैंड**	**प्रति** 100 kHz **स्पेक्ट्रम शुल्क (रुपये में) (**10 **वर्षों के लिए लागू)**
कम शक्ति वाले रडारों (ईआईआरपी<10 वाट)	2690 MHz तक	1,200
	2690 -5000 MHz	
	5000-8500 MHz	300
	8500 -14500 MHz	120
	14500 MHz से अधिक	

सारणी ग: रडार एप्लीकेशन के लिए आवश्यक बैंडविड्थ की गणना

1. आवृत्ति बैंड का निर्धारण प्रेषित सिग्नल की आवश्यक बैंडविड्थ (20 डीबी बैंडविड्थ) के आधार पर किया जाएगा, जहां दूरसंचार उपकरण के ऐसे तकनीकी विवरण आवेदक द्वारा नियम 4 के तहत प्रस्तुत किए गए हों।
2. यदि ऐसी जानकारी नियम 4 के अंतर्गत प्रस्तुत तकनीकी विवरणों में शामिल नहीं है, तो निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाएगा:
(क) नॉन-एफएम रडार के लिए: $B_N = 1.79/\sqrt{t * tr}$ या $\frac{6.36}{t}$; जो भी कम हो
(ख) एफएम पल्स रडार के लिए: $B_N = 1.79/\sqrt{t * tr} + 2B_c$
(ग) एफएम पल्स रडार के लिए (आवृत्ति हॉपिंग के साथ): $B_N = 1.79/\sqrt{t * tr} + 2Bc;$
(घ) नॉन-एफएम पल्स (स्प्रेड स्पेक्ट्रम या कोडेड पल्स सहित) का उपयोग करने वाले आवृत्ति हॉपिंग रडार के लिए: $B_N = 1.79/\sqrt{t * tr} + B_{s;}$
(ङ) एफएम/सीडब्ल्यू रडार के लिए: $B_N = 2B_{d;}$
<u>जहां:</u>
B_N = MHz में आवश्यक बैंडविड्थ;
Bc = MHz में आवृत्ति डेवीएशन का बैंडविड्थ (पल्स अवधि के दौरान कुल आवृत्ति शिफ्ट);
B_d = MHz में आवृत्ति डेवीएशन का बैंडविड्थ (एफएम/सीडब्ल्यू रडार सिस्टम के लिए मॉड्यूलेटेड तरंग की तात्कालिक आवृत्ति और केरियर आवृत्ति के बीच का अधिकतम अंतर);
Bs = MHz में वह अधिकतम सीमा जिसके भीतर आवृत्ति हॉपिंग रडार के लिए केरियर आवृत्ति को स्थानांतरित किया जाएगा;

t = 50% एम्प्लीट्यूड (वोल्टेज) पॉइंट्स पर μ सेकंड में उत्सर्जित पल्स की अवधि। कोडेड पल्स के लिए, पल्स की अवधि एक चिप (सब-पल्स) के 50% एम्प्लीट्यूड पॉइंट्स के बीच का अंतराल होती है। 100% एम्प्लीट्यूड, पल्स का सामान्य फ्लैट टॉप लेवल होता है;
t_r = लीडिंग एज पर 10% से 90% एम्प्लीट्यूड पॉइंट्स के बीच μ सेकंड में उत्सर्जित पल्स का राइज़ टाइम। कोडेड पल्स के लिए, यह सब-पल्स का राइज़ टाइम होता है; अगर सब-पल्स का राइज़ टाइम पता न चल सके, तो इसे एक फ़ेज़ या सब-पल्स से अगले पर स्विच करने में लगने वाले समय का 40% माना जाता है;
एफएम रडार = आवृत्ति मॉड्यूलेटेड रडार;
सीडब्ल्यू रडार = कंटीन्यूअस वेव रडार।

सारणी घ: रेडियो स्टेशन का वार्षिक शुल्क

क्र.सं.	**रेडियो स्टेशन का प्रकार (स्टैंडबाय सेट सहित)**	**रेडियो स्टेशन का वार्षिक शुल्क (रुपये में)**
1.	रडार स्टेशन	प्रति रेडियो स्टेशन 1000

अनुलग्नक-VI: मल्टीप्लेक्स मल्टी-चैनल वाली फिक्सड और मोबाइल सेवाएँ

1. यह अनुलग्नक अनुसूची I की प्रविष्टियों 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 17 के संबंध में मल्टीप्लेक्स मल्टी-चैनल वाली फिक्सड और मोबाइल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन पर लागू होगा।

2. इस अनुलग्नक में ये शामिल हैं:

   (क) सारणी क, सारणी क1 और क2 के आधार पर वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क की गणना का फ़ॉर्मूला बताता है; और

   (ख) सारणी ख में रेडियो स्टेशन की शुल्क बताई गई है।

सारणी क: वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क की गणना करने का फ़ॉर्मूला

कैलकुलेशन का फ़ॉर्मूला इस तरह होगा:

वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क (आर) = एमxसीxडब्ल्यू , जहां: एम-फैक्टर (कवरेज), सी-फैक्टर (आवृत्ति कैरियर की संख्या) और डब्ल्यू-फैक्टर (बैंडविड्थ)

सारणी -क1: एम-फ़ैक्टर की दर

दूरी श्रेणी	अधिकतम दूरी (किमी)	एम-फैक्टर का मूल्य
I.	≤ 2	750
II.	$> 2 \leq 5$	1500
III.	$> 5 \leq 25$	3000
IV.	$> 25 \leq 60$	6000
V.	$> 60 \leq 120$	11000
VI.	$> 120 \leq 500$	18750
VII.	> 500	25000

सारणी -क2: डब्ल्यू-फ़ैक्टर की दर

एड्जसेंट चैनल सेपरेशन के स्लैब (बैंडविड्थ) (MHz में) *(फ़्रैक्शन में कोई भी अमाउंट अगले इंटीजर तक राउंड अप किया जाएगा)।*	डब्ल्यू -फैक्टर का मान
> 375 kHz $\leq$ 2 MHz	*30*

> 2 ≤ 3.5	*40*
> 3.5 ≤ 7	*60*
> 7 ≤ 14	*90*
> 14 ≤ 28	*120*
> 28 ≤ 56	*150*
> 56 ≤ 112	*180*
> 112 ≤ 256	*210*
> 256 ≤ 512	*240*
> 512	*240+ 30 x (अतिरिक्त बैंडविड्थ / 256, यानी* 256 MHz या उसके हिस्से के स्टेप्स में)

सारणी ख: वार्षिक रेडियो स्टेशन शुल्क

क्र. सं.	**रेडियो स्टेशन का प्रकार**	**वार्षिक रेडियो स्टेशन की शुल्क (रु . में)**
1.	निश्चित रेडियो स्टेशन	प्रति रेडियो स्टेशन 1000
2.	वेहिकल मोबाइल/हैंडहेल्ड मोबाइल रेडियो स्टेशन	250 प्रति रेडियो स्टेशन

अनुलग्नक-VII: सैटेलाइट आधारित सेवाएँ

1. यह अनुलग्नक अनुसूची I की प्रविष्टि 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16(क), 16(ख), 16(ग), 16(घ), 16(ङ), 16(च)(1) (कैप्टिव वीसैट तक सीमित), 16(छ), 16(ज) और 17 के संबंध में सैटेलाइट आधारित सेवाओं (फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विसेज (एफएसएस), ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट सर्विसेज (बीएसएस), मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज (एमएसएस) और पृथ्वी अन्वेषण सैटेलाइट सर्विसेज (ईईएसएस)/ मौसम संबंधी सैटेलाइट सेवा सहित) के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन पर लागू होगा और सैटेलाइट-आधारित वाणिज्यिक संचार सेवाओं पर लागू नहीं होता है।

2. इस अनुलग्नक में ये शामिल हैं:

   (क) भाग I सारणी 1 के पठित है जिसमें स्पेक्ट्रम शुल्क बताया गया है; और

   (ख) भाग II को सारणी 2 के साथ पठित, जिसमें सैटेलाइट सर्विसेज़ के तहत काम करने वाले अर्थ स्टेशनों के लिए रेडियो स्टेशन शुल्क बताया गया है।

3. इस अनुलग्नक के प्रयोजन के लिए, "आईओटी" का अर्थ इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जिसमें इंटरनेट पर एम2एम संचार शामिल है।

भाग I: स्पेक्ट्रम शुल्क पर लागू शर्तें

1. स्पेक्ट्रम शुल्क, असाइन किए गए कुल बैंडविड्थ पर देनी होगी, जिसमें कोई भी गार्ड बैंड शामिल है, और भारत से या भारत के क्षेत्र में ट्रांसमिट की गई आवृत्ति के संबंध में भी देनी होगी।

2. अर्थ एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट सर्विस / मौसम सैटेलाइट सर्विस के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क गणना करने के लिए, दूरसंचार नेटवर्क में रिमोट यूज़र्स या कनेक्शन की संख्या चाहे जो भी हो, सिर्फ़ एक रिमोट टर्मिनल को ध्यान में रखा जाएगा।

3. डिजिटल सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग (डीएसएनजी) / सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग (एसएनजी) के संबंध में स्पेक्ट्रम शुल्क, अपलिंक और डाउनलिंक दोनों पर इस्तेमाल होने वाली आवृत्ति के लिए देनी होगी।

4. अगर असाइनी के एक से ज़्यादा डीएसएनजी वैन से एक ही आवृत्ति कैरियर का प्रयोग किया जाता है, तो ये लागू होगा:

   (क) पहली डीएसएनजीवैन के लिए, इस अनुलग्नक में बताई गई वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क ली जाएगी; और

(ख) प्रत्येक अतिरिक्त डीएसएनजी वैन के लिए, इस अनुलग्नक में निर्दिष्ट वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क के 25% की दर से स्पेक्ट्रम शुल्क लिया जाएगा।

बशर्ते कि उसी जगह पर तैनात ऐसे अतिरिक्त डीएसएनजी वैन के लिए कोई स्पेक्ट्रम शुल्क नहीं ली जाएगी।

5. सर्विसेज़ के लिए वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क) टीटीसी ऑपरेशन) का शुल्क 1,50,000/- रुपये प्रति अर्थ स्टेशन की दर से देय होगा ।

6. स्पेक्ट्रम शुल्क डेटा कलेक्शन प्लेटफॉर्म के रिमोट टर्मिनलों और एमएसएस में लोकेशन और अन्य डेटा देने के लिए इस्तेमाल होने वाले आईओटी टर्मिनलों पर लागू नहीं होगी।

7. ऊपर दिए गए पॉइंट 1 से 5 में शामिल नहीं किए गए बाकी सभी मामलों में, स्पेक्ट्रम शुल्क हर साल देनी होगी, जिसकी कैलकुलेशन इस फ़ॉर्मूले के हिसाब से की जाएगी:

<u>वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क (आर) = Rs . 35000xBs, जहाँ Bs का अभिप्राय है बैंडविड्थ फैक्टर, जिसे सारणी 1 में दिए गए तरीके से कैलकुलेट किया गया है।</u>

सारणी । : बैंडविड्थ फैक्टर (Bs) की गणना

क्र. सं	कुल असाइनड बैंडविड्थ		बैंडविड्थ फैक्टर (Bs)			
			अपलिंक के लिए		डाउनलिंक के लिए	
			प्रसारण*	अन्य	प्रसारण*	अन्य
(i)	500 kHz तक (अर्थात्, बीडब्ल्यू ≤ 500 kHz)	100 kHz तक (अर्थात्, बीडब्ल्यू ≤ 100 kHz)	0.25	0.20	शून्य	0.20
(ii)		100 kHz से ज़्यादा और 250 kHz तक (अर्थात्, 100 kHz < बीडब्ल्यू ≤ 250 kHz)	0.60	0.50	शून्य	0.50
(iii)		250 kHz से ज़्यादा और 500 kHz तक (अर्थात्, 250 kHz < बीडब्ल्यू ≤ 500 kHz)	1.25	1.00	शून्य	1.00
(iv)	500 kHz से अधिक (यानी, बीडब्ल्यू > 500 kHz)		कुल बीएस			

*इस सारणी में प्रयोग किया गया शब्द "ब्रॉडकास्ट" का अभिप्राय सैटेलाइट के द्वारा टेलीविज़न कंटेंट का ट्रांसमिशन है, जिसमें टेलीपोर्ट, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग (डीएसएनजी) वैन, डायरेक्ट टू होम (डीटीएच), और हेडएंड इन द स्काई (एचआईटीउस) शामिल हैं।

बैंडविड्थ फैक्टर की गणना इस प्रकार की जाएगी:

कुल बीएस = [ऊपर की पंक्ति (iii) से उपयुक्त Bs X बैंडविड्थ 500 kHz के गुणज की संख्या में] + [वृद्धिशील Bs]

जहाँ,

i. इंक्रीमेंटल Bs= [ऊपर दी गई रो (i) से सही Bs, बैलेंस बैंडविड्थ में 100 kHz या उसके हिस्से के मल्टीपल की X संख्या]; और

ii. बैलेंस बैंडविड्थ = [बैंडविड्थ/ 500 kHz] का शेष हिस्सा

भाग II: सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज़ के तहत काम करने वाले अर्थ स्टेशनों के लिए रेडियो स्टेशन शुल्क

1. सैटेलाइट-आधारित सेवाओं के तहत काम करने वाले अर्थ स्टेशनों (एग्रीगेटर या डायरेक्ट-टू-सैटेलाइट मोड में आईओटी या आईओटी डिवाइस के अलावा) के लिए रेडियो स्टेशन शुल्क सारणी 2 में दिए गए शुल्क के अनुसार होगा।

2. आईओटी और एग्रीगेटर या डायरेक्ट-टू-सैटेलाइट मोड में आईओटी डिवाइस के लिए रेडियो स्टेशन शुल्क नहीं देना होगा।

सारणी 2: वार्षिक रेडियो स्टेशन शुल्क

क्र.सं.	अर्थ स्टेशन का प्रकार (स्टैंडबाय सेट सहित)	वार्षिक रेडियो स्टेशन शुल्क (रु. में)
1.	फिक्स्ड अर्थ स्टेशन/ डायरेक्ट टू होम (डीटीएच)/ टेलीपोर्ट/ डिजिटल सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग (डीएसएनजी)/ लॉन्ग डिस्टेंस (एलडी) /डीसीपी/ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स-II (आईपी-II)	प्रति स्टेशन 1000
2.	कैप्टिव वीसैट अर्थ स्टेशन	500 प्रति स्टेशन
3.	वेहिकल मोबाइल/हैंडहेल्ड मोबाइल रेडियो स्टेशन	250 प्रति रेडियो स्टेशन

अनुलग्नक -VIII: पीएमआरटी सेवा

1. यह अनुलग्नक, अनुसूची । की प्रविष्टि 11 के तहत पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन पर लागू होगा।

2. इस अनुलग्नक में शामिल हैं :

   (क) <u>भाग क,</u> जिसमें सालाना स्पेक्ट्रम शुल्क बताया गया है; और

   (ख) <u>भाग ख,</u> जिसमें रेडियो स्टेशन शुल्क बताया गया है।

<u>भाग क: वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क</u>

समनुदेशिती निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का उपयोग करके सालाना स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान करेगा:

विकल्प 1: स्पेक्ट्रम शुल्क का वार्षिक भुगतान

1. उसी सर्विस एरिया के अंदर शहर में 30 किंमी तक की लिंक दूरी के लिए, प्रति 6.25 kHz चैनल के लिए 1,200 रुपये (केवल एक हज़ार दो सौ रुपये) सालाना।

2. उसी सर्विस एरिया के अंदर शहर में 60 किंमी तक की लिंक दूरी के लिए, प्रति 6.25 kHz चैनल के लिए ₹2400 रुपये (केवल दो हज़ार चार सौ रुपये) सालाना।

विकल्प 2: स्पेक्ट्रम शुल्क का एक बार में अग्रिम भुगतान

पांच साल की अवधि के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क का एकमुश्त अग्रिम भुगतान इस प्रकार है:

1. उसी सर्विस एरिया के अंदर शहर में 30 किंमी तक की लिंक दूरी के लिए, प्रति 6.25 kHz चैनल के लिए 5,000 रुपये (केवल पाँच हज़ार रुपये)।

2. उसी सर्विस एरिया में 60 किंमी तक की लिंक दूरी के लिए हर 6.25 kHz चैनल के लिए 10,000 रुपये (सिर्फ़ दस हज़ार रुपये)।

भाग ख: रेडियो स्टेशन शुल्क

रेडियो स्टेशन शुल्क एजीआर का एक प्रतिशत होगी और इसका भुगतान दूरसंचार (विविध दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 के अनुसार किया जाएगा।

अनुलग्नक IX: सैटेलाइट- आधारित वाणिज्यिक संचार सेवाएँ

1. यह अनुलग्नक अनुसूची I की प्रविष्टियों 16(च)(2) (वीसैट वाणिज्यिक तक सीमित) और 16(झ) के संबंध में सैटेलाइट-आधारित वाणिज्यिक संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के समनुदेशन पर लागू होगा।

2. स्पेक्ट्रम प्रभार की गणना समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशत के रूप में की जाएगी जेसा की नीचे दिया गया है:

सैटेलाइट सेवा का प्रकार	**सालाना स्पेक्ट्रम प्रभार की गणना का फ़ॉर्मूला**	
भू-स्थिर कक्षा में वीसैट वाणिज्यिक	**उपयोगकर्ता डेटा दर की सीमा**	**स्पेक्ट्रम प्रभार**
	128 केबीपीएस तक	एजीआर का 3.0%
	128 केबीपीएस से ज़्यादा और 512 केबीपीएस तक	एजीआर का 3.5%
	512 केबीपीएस से ज़्यादा और 2 एमबीपीएस तक	एजीआर का 4.0%
भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा सुई जेनेरिस कैटेगरी के तहत ग्लोबल सैटेलाइट फोन सर्विस (जीएसपीएस)	एजीआर का 1%	

अनुलग्नक-X: रेडियो बैकहॉल

1. यह अनुलग्नक, अनुसूची ।की प्रविष्टि 12 के तहत रेडियो बैकहॉल के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन पर लागू होगा।

2. स्पेक्ट्रम प्रभार की गणना एजीआर के प्रतिशत के रूप में संचयी रूप से की जाएगी, जैसा कि नीचे बताया गया है:

स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ	**स्पेक्ट्रम प्रभार की गणना का फ़ॉर्मूला, जो कुल मिलाकर कैलकुलेट किया जाता है और सालाना देना होता है (एजीआर का %)**
माइक्रोवेव एक्सेस और माइक्रोवेव बैकबोन	
28 MHz का पहला कैरियर (युग्मित)	0.15%
28 MHz का दूसरा कैरियर (युग्मित)	0.35%
28 MHz का तीसरा कैरियर (युग्मित)	0.55%
28 MHz का चौथा कैरियर (युग्मित)	0.80%
28 MHz का पांचवां कैरियर (युग्मित)	1.10%
28 MHz का छठा कैरियर (युग्मित)	1.45%
28 MHz का सातवां कैरियर (युग्मित)	1.85%
28 MHz का आठवां कैरियर (युग्मित)	2.30%
28 MHz का नौवां कैरियर (युग्मित)	2.80%
28 MHzका दसवां कैरियर (युग्मित)	3.35%
28 MHzका ग्यारहवां कैरियर (युग्मित)	3.95%
ई बैंड	
250 MHz (युग्मित) का पहला कैरियर	0.15%
250 MHzका दूसरा कैरियर (युग्मित)	0.30%

अनुलग्नक-XI: एक्सेस स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम प्रभार

1. यह अनुलग्नक स्पेक्ट्रम समनुदेशन पर लागू होगा:

   (क) अनुसूची I की प्रविष्टि 18 के संबंध में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल);

   (ख) अनुसूची I की प्रविष्टि 4 के संबंध में तीन महीने से अधिक की अवधि नहीं; और

   (ग) अनुसूची I की प्रविष्टि 6 के तहत मेट्रो और क्षेत्रीय रेल प्रणालियों की सुरक्षा और संचालन।

2. जैसा कि राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार के कार्यान्वयन के लिए चिह्नित किया गया है, आवृत्ति बैंड या उसके भागों में जैसा कि केंद्रीय सरकार पोर्टल पर निर्दिष्ट कर सकती है, उनमें प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से एक्सेस स्पेक्ट्रम का आवंटन, बाज़ार मूल्य के आधार पर होगा।

   स्पष्टीकरण - इस अनुलग्नक के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "बाजार मूल्य" का तात्पर्य आरक्षित मूल्य या एक्सेस स्पेक्ट्रम की कीमत से है, जो स्पेक्ट्रम समनुदेशन की प्रभावी तिथि से पहले प्रकाशित अंतिम एनआईए के अनुसरण में आयोजित नीलामी के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, जो भी अधिक हो:

   बशर्ते कि जहां ऐसी नीलामी स्पेक्ट्रम समनुदेशन की प्रभावी तारीख से बारह महीने से अधिक पहले आयोजित की गई हो, नीलामी के तहत निर्धारित ऐसा आरक्षित मूल्य या मूल्य, जैसा भी मामला हो, भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट पर अधिसूचित भारतीय स्टेट बैंक की निधियों पर आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की प्रासंगिक सीमांत लागत का उपयोग करके निकाला जाएगा।

अनुलग्नक-XII: एक या अधिक विनियामक सैंडबॉक्स के सृजन सहित नई प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन को सक्षम बनाने के लिए टेस्टिंग, ट्रायल, प्रयोगात्मक, प्रदर्शन उद्देश्य

1. यह अनुलग्नक अनुसूची-I की प्रविष्टि 19 के संबंध में एक या अधिक विनियामक सैंडबॉक्स के सृजन सहित नई प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन को सक्षम बनाने के लिए टेस्टिंग, ट्रायल, प्रयोगात्मक, प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन पर लागू होगा।

2. समनुदेशिती इस अनुलग्नक के तहत स्पेक्ट्रम असाइंगमेंट के संबंध में, -

   (क) यह सुनिश्चित करना कि किसी भी टेस्टिंग, ट्रायल, प्रयोगात्मक, प्रदर्शन से किसी अन्य प्राधिकृत संस्था या समनुदेशिती के किसी भी दूरसंचार उपकरण, दूरसंचार नेटवर्क या दूरसंचार सेवा में हस्तक्षेप नहीं होता है; और

   (ख) किसी अन्य प्राधिकृत संस्था या समनुदेशिती के किसी भी दूरसंचार उपकरण, दूरसंचार नेटवर्क या दूरसंचार सेवा के कारण होने वाले हस्तक्षेप से सुरक्षा का दावा नहीं करता है।

   स्पष्टीकरण- इस प्रावधान में, "हस्तक्षेप" अभिव्यक्ति का अभिप्राय रेडियो संचार प्रणाली में प्राप्ति पर एक या एक से अधिक इमिशन रेडियेशन या इन्डक्शन के संयोजन के कारण अवांछित ऊर्जा के प्रभाव है जो ऐसी किसी अवांछित ऊर्जा की गैरमौजूदगी मे निष्पादन में गिरावट, गलत व्याख्या या सूचना नहीं मिलने के परिणामस्वरूप होता है।

3. इस अनुलग्नक के तहत स्पेक्ट्रम का कोई भी आवंटन गैर-हस्तक्षेप और गैर-सुरक्षा के आधार पर किया जाएगा और इसका उपयोग नियमित उपयोग या प्रयोक्ताओं को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए नहीं किया जाएगा।

4. इस अनुलग्नक के तहत स्पेक्ट्रम के आवंटन पर लागू शर्तें इस प्रकार हैं:

   (क) टेस्टिंग:

      (i) टेस्टिंग से वायरलेस दूरसंचार उपकरण या प्रणालियों के रेडियो आवृत्ति टेस्टिंग का अस्थायी प्रचालन, जिसमें तकनीकी मूल्यांकन, सत्यापन या प्रमाणन के उद्देश्य से प्रोडक्ट टेस्टिंग, कम्पलायन्स टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, फील्ड टेस्टिंग, नेटवर्क टेस्टिंग और विनियामक टेस्टिंग, वाणिज्यिक संचालन या दूरसंचार सेवाओं का वितरण शामिल हैं लेकिन यह यही तक सीमित नहीं हैं।

      (ii) टेस्टिंग के संबंध में स्पेक्ट्रम का आवंटन इनडोर और आउटडोर एनवायरनमेंट के लिए रेडिएशन मोड में किया जाएगा, जहां ईआईआरपी 100 मिलीवाट से अधिक है।

(iii) इनडोर और आउटडोर एनवायरनमेंट में, रेडिएशन मोड में, जहां ईआईआरपी 100 मिलीवाट से कम है, को स्पेक्ट्रम के समनुदेशन की आवश्यकता से छूट दी गई है।

(iv) टेस्टिंग करने वाला समनुदेशिती यह सुनिश्चित करेगा कि टेस्टिंग के दौरान संबंधित प्रौद्योगिकियों, उत्पादों, प्रक्रियाओं या व्यावसायिक मॉडल को इस तरह के टेस्टिंग की अवधि के दौरान बाजार में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

(ख) ट्रायल:

(i) स्पेक्ट्रम का आवंटन प्रौद्योगिकी और क्षमता के प्रदर्शन, प्रोडक्ट स्टैबलाइजेशन, इकोसिस्टम के विकास और इसी तरह के अन्य उद्देश्यों से दूरसंचार सेवाओं के वाणिज्यिक लॉन्च से पहले किए गए ट्रायल के लिए किया जाएगा।

(ii) ट्रायल करने वाला समनुदेशिती यह सुनिश्चित करेगा कि ट्रायल के दौरान संबंधित प्रौद्योगिकियों, उत्पादों, प्रक्रियाओं या व्यावसायिक मॉडल को इस तरह के ट्रायल की अवधि के दौरान बाजार में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

(iii) ट्रायल पूरी होने पर, समनुदेशिती केंद्रीय सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें इस तरह के ट्रायल के परिणामस्वरूप किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकारों के परिणाम और सृजन शामिल होंगे।

(ग) प्रायोगिक:

(i) प्रायोगिक से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रयोगों में रेडियो तरंगों का उपयोग अभिप्रेत है।

(ii) प्रयोग के संबंध में स्पेक्ट्रम का समनुदेशन इनडोर और आउटडोर एनवायरनमेंट के लिए रेडिएटिंग मोड में किया जाएगा, जहां ईआईआरपी 100 मिलीवाट से अधिक है।

(iii) इनडोर और आउटडोर एनवायरनमेंटमें, विकिरण मोड में, जहां ईआईआरपी 100 मिलीवाट से कम है, को स्पेक्ट्रम के समनुदेशन की आवश्यकता से छूट दी गई है।

(iv) प्रयोग करने वाला समनुदेशिती यह सुनिश्चित करेगा कि प्रयोग के दौरान संबंधित प्रौद्योगिकियों, उत्पादों, प्रक्रियाओं या व्यावसायिक मॉडल को इस तरह के प्रयोग की अवधि के दौरान बाजार में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

(v) प्रयोग करने वाला समनुदेशिती यह सुनिश्चित करेगा कि इस संबंध में केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, भारत में प्रायोगिक वायरलेस स्टेशन और भारत के बाहर किसी भी देश में स्थित ऐसे समान स्टेशन के बीच कोई संचार नहीं होगा।

(vi) प्रयोग पूरा होने पर, समनुदेशिती केंद्रीय सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें इस तरह के प्रयोग के परिणामस्वरूप किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकारों के परिणाम और निर्माण शामिल होंगे।

(घ) प्रदर्शन:

(i) प्रदर्शन में तकनीकी डिस्प्ले, प्रदर्शनी, प्रूफ ऑफ कान्सेप्ट, मूल्यांकन और बिक्री के लिए प्रदर्शन, विनिर्दिष्ट स्थानों पर, सीमित अवधि के लिए, किसी भी दूरसंचार सेवा के प्रावधान के बिना या राजस्व के किसी भी उत्पादन के बिना शामिल है।

(ii) प्रदर्शन के संबंध में स्पेक्ट्रम का आवंटन आउटडोर एनवायरनमेंट के लिए रेडिएटिंग मोड में किया जाएगा, जहां ईआईआरपी 100 मिलीवाट से अधिक है।

(iii) इनडोर और आउटडोर एनवायरनमेंट में प्रदर्शन, विकिरण मोड में, जहां ईआईआरपी 100 मिलीवाट से कम है, को स्पेक्ट्रम के समनुदेशन की आवश्यकता से छूट दी गई है।

5. लागू स्पेक्ट्रम प्रभार नीचे विनिर्दिष्ट किया गया है:

विवरण	**स्पेक्ट्रम** समनुदेशन **पत्र की अवधि के लिए स्पेक्ट्रम प्रभार**
टेस्टिंग	1,000/- रु. प्रति आवृत्ति बैंड
ट्रायल	1,000/- रु.प्रति आवृत्ति बैंड
प्रायोगिक	1,000/- रु.प्रति आवृत्ति बैंड
प्रदर्शन	1,000/- रु.प्रति आवृत्ति बैंड

अनुलग्नक-XIII: स्पेक्ट्रम प्रभार के भुगतान में देरी के लिए विलंब शुल्क

1. यह अनुलग्नक विनिर्दिष्ट अनुसूची II के प्रासंगिक अनुलग्नक के साथ पठित अनुसूची-I की निम्नलिखित प्रविष्टियों के संबंध में स्पेक्ट्रम प्रभार के विलंबित भुगतान के संबंध में लागू होगा:

क्र.सं.	अनुसूची I की प्रविष्टियां
1	राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा।
2	विधि प्रवर्तन और अपराध रोकथाम।
3	लोक प्रसारण सेवाएं।
4	आपदा प्रबंधन, जीवन और संपत्ति की रक्षा।
5	वैज्ञानिक अनुसंधान, संसाधन विकास और खोज का संवर्धन
6	सड़कों, रेल मार्गों, मैट्रो, क्षेत्रीय रेल, अन्तरदेशीय जलमार्गों, विमानपत्तनों, पाइप लाइनों, पोत परिवहन और अन्य यातायात प्रणालियों की सुरक्षा और प्रचालन।
7	प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीवन का संरक्षण।
8	मौसम विभाग और मौसम पूर्वानुमान।
9	अव्यवसायी स्टेशनों, नौ-परिवहन, दूरमिति और अन्य समान उपयोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त समर्पित बैंड।
10	खानें, पत्तनों और तेल की खोज की सुरक्षा और प्रचालनों तथा ऐसे अन्य क्रियाकलापों के लिए, जहां स्पैक्ट्रम का उपयोग प्राथमिक रूप से सुरक्षा और प्रचालनों का समर्थन करने के लिए है, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, या उनके अस्तित्वों या अन्य प्राधिकृत अस्तित्वों द्वारा उपयोग।
11	पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवाएं, स्पेक्ट्रम शुल्क के भुगतान तक सीमित।
13	सामुदायिक रेडियो स्टेशन।
15	अंतरिक्ष अनुसंधान और अनुप्रयोग, प्रस्थान यान प्रचालन और सैटेलाइट नियंत्रण के लिए आधार स्टेशन
16	कुछ सेटेलाइट -आधारित सेवाएँ जैसे:
16 (क)	टेलीपोर्ट
16 (ख)	टेलीविजन चैनल
16 (ग)	डायरेक्ट टू होम
16 (घ)	हैडएंड इन द स्काई

क्र.सं.	**अनुसूची I की प्रविष्टियां**
16 (ङ)	डिजिटल सैटेलाइट समाचार एकत्रीकरण
16(च) (1)	वैरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल (कैप्टिव)
16 (छ)	राष्ट्रीय लंबी दूरी
16 (ज)	अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी
17	दूरसंचार सेवाओं के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या उनकी प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा उपयोग।

2. भुगतान के लिए नियत तिथि की आधी रात के बाद केंद्रीय सरकार के खाते में दर्शाई गई किसी भी भुगतान को भुगतान में देरी के रूप में माना जाएगा, बशर्ते समनुदेशिती द्वारा भुगतान लेनदेन शुरू कर दिया गया हो।

3. पैरा 2 के तहत उल्लिखित किसी भी देरी से भुगतान की स्थिति में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लागू विलंब शुल्क की गणना भारतीय स्टेट बैंक की उधार दर (एमसीएलआर) दो प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि की सीमांत लागत की दर से की जाएगी:

बशर्ते कि लागू न्यूनतम विलंब शुल्क केवल दो सौ पचास रुपये होंगे:

बशर्ते कि विलंब प्रभारों की गणना के प्रयोजन के लिए महीने के एक हिस्से को पूरे महीने के रूप में माना जाएगा।

[फा. सं. 24-02/2025-यूबीबी]

देवेंद्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2026

G.S.R. 494(E).—The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 and sub-section (2) of section 8 read with sub-section (1) and clauses (g) and (m) to sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public:

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecommunications), Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New Delhi- 110001:

The objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government.

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Telecommunications (Spectrum Assignment by Administrative Process) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on such date as the Central Government may specify by notification in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);

(b) "letter of intent" means the letter issued under sub-rule (1) of rule 6;

(c) "portal" means the portal referred to in rule 14;

(d) "spectrum assignment" means the permission issued under sub-rule (4) of rule 6, for use of spectrum by a radio station; and

(e) "spectrum charge" means the spectrum fees and the fees for the radio station or radio equipment, specified in the relevant annexure to Schedule II.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act, the rules made thereunder or the National Frequency Allocation Plan published by the Central Government shall have the meanings respectively assigned to them in the Act, the said rules or the said plan.

3. Scope and applicability.—(1) These rules prescribe the terms and conditions of spectrum assignment by administrative process, in respect of the entries listed in the First Schedule to the Act.

(2) Schedule I to these rules specifies persons who may apply for spectrum assignment by administrative process in respect of entries of the First Schedule to the Act, the specific usages for such entries, along with the annexures of Schedule II applicable to such entries, and Schedule II to these rules and the annexures thereto specify terms and conditions of spectrum assignment that are specific to each annexure, and methodology for determination of spectrum charges.

4. Eligibility Conditions.—(1) Any person applying for spectrum assignment under these rules shall meet the eligibility criteria specified in this rule and in the relevant entry of Schedule I.

(2) If the person applying for spectrum assignment is a person other than the Central Government, State Government, agency designated by such government, a statutory body established under law, then it shall satisfy the following eligibility criteria, namely:—

(a) If such person is a company, the foreign direct investment, if any, in such company, shall be in conformity with the extant laws and policies of India; and

(b) If such person is a company, the key managerial personnel in such company shall fulfil such security related criteria as the Central Government may specify on the portal.

Explanation.—For the purposes of these rules, the expression—

(a) "licence" means a licence, registration or permission, by whatever name called, granted under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and

(b) "foreign direct investment" shall have the same meaning as is assigned to it in the rules made in respect of non-debt instruments under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999).

(3) The persons specified under sub-rules (1) to (2) shall also comply with any other criteria as may be specified by the Central Government on the portal for the purposes of spectrum assignment under the relevant entry of the First Schedule to the Act.

CHAPTER II
APPLICATION AND GRANT OF SPECTRUM ASSIGNMENT

5. Application.—(1) Any person intending to obtain spectrum assignment under these rules shall submit an application, in such form and manner and accompanied by payment of non-refundable application fees of one thousand rupees and such information and documents as the Central Government may specify on the portal, including—

(a) specified usage of spectrum;

(b) type of authorisation or licence held by the applicant, if applicable;

(c) proof of successful demonstration of the lawful interception systems, lawful interception monitoring facilities and any other additional functional requirement that the Central Government may specify, if applicable;
(d) the geographical area of operation;
(e) estimated type and quantity of radio equipment required, along with technical data sheet of such equipment;
(f) frequency range and transmission parameters, including bandwidth, mode, emission designator, transmit power, EIRP levels required for usage of spectrum, and the information of the satellite network used, along with its orbital parameters and radiocommunication service, if applicable;
(g) proposed duration for which spectrum assignment is sought; and
(h) permissions under applicable law, relevant to the sector for which assignment is sought, if applicable.

Provided that where such equipment is equipment that blocks telecommunication, the person seeking assignment in respect of the same shall, along with such application, submit the permission obtained under section 48 of the Act.

(2) If the applicant under sub-rule (1) intends to install radio equipment at a fixed site, it shall apply to obtain the applicable clearance, in such form and manner along with applicable fees, as the Central Government may specify on the portal:

Provided that if the Central Government rejects the application under this sub-rule, the applicant may apply afresh for such clearance, specifying an alternate site for installation of radio equipment:

Provided further that applicants seeking spectrum assignment in respect of the following entries of the First Schedule to the Act may apply for such clearance after the grant of spectrum assignment, namely:—

(a) Entry 1: National security and defence;
(b) Entry 2: Law enforcement and crime prevention;
(c) Entry 11: Public Mobile Radio Trunking Services;
(d) Entry 12: Radio backhaul for telecommunication services; and
(e) Entry 18: Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) and Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL).

Explanation.—For removal of doubts, it is clarified that there shall be no installation of radio equipment at a fixed site without obtaining prior applicable clearance under sub-rule (2).

6. **Grant of spectrum assignment**.—(1) The Central Government shall, after making such inquiry as it deems fit, require the applicant to furnish such information as it may call for and may, subject to obtaining the applicable clearance under sub-rule (3) of rule 5, and subject to the availability of spectrum and relevant security clearances, where applicable, issue a letter of intent:

Provided that the Central Government may, in public interest, issue a letter of intent prior to obtaining such applicable clearance, in respect of entries of the First Schedule to the Act other than those specified in the second proviso of sub-rule (3) of rule 5.

(2) The letter of intent issued under sub-rule (1) shall specify the following, namely:—

(a) The relevant entry of First Schedule to the Act and specific usages of spectrum assignment, along with the applicable annexures of Schedule II;
(b) Applicable spectrum charges and timelines for payment of such charges;
(c) Frequency range and transmission parameters, including bandwidth, mode, emission designator, transmit power, EIRP levels required for usage of spectrum, and the information of the satellite network used, along with its orbital parameters and radiocommunication service, if applicable;
(d) Geographical area of operation;
(e) Relevant radio stations and location of such stations; and
(f) Type and quantity of radio equipment.

(3) The recipient of the letter of intent shall, within the timelines as specified in such letter,—

(a) make payment of the component of spectrum charges as specified in such letter; and
(b) procure the relevant radio equipment.

(4) On being satisfied that the requirements specified in the letter of intent are fulfilled by the applicant, the Central Government shall grant spectrum assignment through the portal, specifying, among other things, the following, namely:—

(a) details as specified in the letter of intent; and
(b) effective date and duration of spectrum assignment.

Provided that if the Central Government has issued a letter of intent prior to obtaining the applicable clearance for the installation of radio equipment, the spectrum assignment shall be granted, after such clearance has been obtained.

Explanation.— For the removal of doubts, it is clarified that if the duration for which spectrum assignment is granted is less than a period of one calendar month, the spectrum charges for the entire calendar month shall apply.

(5) An assignee may possess radio equipment as specified in its spectrum assignment, without requiring a separate authorisation under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Act.

(6) The Central Government may specify on the portal, the maximum duration of spectrum assignment and limits on the number of spectrum assignments that may be granted under these rules in respect of one or more entries of the First Schedule to the Act.

7. General terms and conditions.— An assignee shall adhere to the following terms and conditions, namely:—

(a) Maintain an updated inventory of permitted radio equipment and ensure its secure custody and operation only by authorised personnel;

(b) Adhere to the eligibility conditions specified in rule 4 throughout the duration of spectrum assignment;

(c) Ensure that its radio stations are operated only for the specific usages for which spectrum assignment has been granted;

(d) Take all necessary measures to ensure that its telecommunication network shall not cause interference to other permitted telecommunication network;

(e) Not connect its telecommunication network with public telecommunication networks including public switched telephone network, public land mobile network, global mobile personal communication by satellite, or internet, unless permitted by Central Government;

(f) Ensure that its telecommunication network is in conformity with standards, as applicable, that the Central Government may specify, including those notified under section 19 of the Act;

(g) Not assign or transfer its spectrum assignment without the prior written approval of the Central Government;

(h) Comply with any security-related directions issued by the Central Government in the interest of national security, public safety, sovereignty and integrity of India;

(i) Forthwith report any instance of unauthorised access, interception, spoofing, cloning, jamming or other security incident affecting its telecommunication network, on the portal, in such form and manner as may be specified thereon in this behalf;

(j) Extend all necessary assistance and cooperation to the Central Government and any agency authorised by it, for—

  (i) matters relating to misuse, compromise or unlawful operation of its radio equipment; and

  (ii) monitoring and enforcement, to ensure adherence to terms and conditions of spectrum utilisation and enable interference-free use of the assigned spectrum; and

(k) Forthwith report any instance of loss, theft, loss of possession or suspected misuse of its radio equipment, on the portal, in such form and manner as may be specified thereon in this behalf.

8. Modification or variation of terms and conditions of spectrum assignment.—(1) An assignee seeking any change in the particulars of the radio stations, the frequency or any other technical parameters, from those specified in the spectrum assignment, shall submit an application on the portal, along with non-refundable fees of one thousand rupees, in such form as the Central Government may specify on the portal.

(2) The Central Government may, upon examination of an application under sub-rule (1) and subject to the availability of spectrum, relevant security clearances where applicable, and payment

of applicable spectrum charges, approve such application and grant an updated spectrum assignment.

(3) The Central Government may also, *suo motu*, modify, vary or make technical adjustments to the terms and conditions of assignment, including by making changes to the usage of frequency bands, power or types of emission, if it is satisfied that it is expedient to do so, having regard to—

(a) the provisions of the National Frequency Allocation Plan;
(b) the need for enforcement of better technical standards to promote efficient spectrum utilisation in respect of equipment;
(c) the national and international radio interference mitigation requirements; and
(d) any rules in respect of re-farming, harmonisation or optimal utilisation of spectrum, that the Central Government may prescribe.

(4) The Central Government shall, pursuant to any modification or variation under sub-rule (3), grant an updated spectrum assignment to the relevant assignee.

(5) The assignee shall implement any modification or variation under this rule within the timelines as specified by the Central Government on the portal.

(6) Any modification or variation of the spectrum assignment under this rule shall not affect the duration specified in the spectrum assignment originally issued to the assignee.

CHAPTER III
RENEWAL AND SURRENDER

9. Renewal—(1) An assignee holding spectrum assignment in respect of any entry of the First Schedule to the Act other than entry 18, namely, Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) and Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL), may submit an application for renewal of spectrum assignment, at least one month prior to the date of its expiry, in such form and manner and along with such spectrum charges as the Central Government may specify on the portal.

(2) On receipt of a written request from an assignee, the Central Government may permit an application after the period specified in sub-rule (1), if it is satisfied that there was sufficient cause for not making such application within such period, subject to payment of such late fees as the Central Government may specify in response to such request.

(3) Any application under sub-rule (1) for renewal of spectrum assignment, issued in respect of trial or experimental under entry 19 of the First Schedule to the Act, shall be accompanied by supporting documents evidencing the outcome of such trial or experiment, and the reasons for seeking such renewal.

(4) The Central Government may, in its discretion, on receipt of an application under sub-rules (1) or (2), renew the spectrum assignment for such period as may be decided by the Central Government, subject to these rules and adherence to law and policy applicable at the time of such renewal.

(5) Spectrum assignment in respect of entry 18 of the First Schedule to the Act, namely, Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) and Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL), shall not be eligible for renewal and the relevant assignee may submit a fresh application under rule 5 to obtain spectrum assignment.

10. Surrender of spectrum.—(1) An assignee seeking to surrender spectrum shall submit an application, in such form and manner as the Central Government may specify on the portal, at least thirty days prior to the proposed date of surrender, accompanied by proof of payment of spectrum charges or any other applicable dues payable by it till the date of the application, and such other information in such form as the Central Government may specify on the portal.

(2) The Central Government may approve or reject an application under sub-rule (1), and if approved, the effective date of surrender shall be the thirty-first day from the date of receipt of such application, or the proposed date of surrender, whichever is later.

(3) After the surrender of spectrum, if the Central Government determines that there are any balance amounts after settlement of all dues payable by the assignee, it may either adjust such amounts pending against other active assignments of the assignee or refund such amount to the assignee.

(4) Every assignee surrendering its spectrum under this rule shall pay all amounts due and payable to the Central Government including spectrum charges, payable till the effective date of surrender as referred to in sub-rule (2).

(5) Surrender of spectrum in respect of entry 18 of the First Schedule to the Act shall be done in accordance with the Telecommunications (Spectrum Assignment through Auction) Rules, 2026.

11. Disposal of radio equipment.—(1) On occurrence of any event as specified in Table 1 below, the relevant assignee shall dispose of the radio equipment specified in the spectrum assignment in accordance with the period specified in Table I below—

TABLE I

Sl. No.	Event relating to disposal	Timeline for disposal
1.	Expiration of spectrum assignment on account of non-renewal.	Within three months of such expiry.
2.	Acceptance by the Central Government of an application for surrender made under rule 10.	Within two months from the effective date of such surrender.
3.	Revocation of assignment pursuant to an order by the Central Government under rule 7.	Within two months from the date of such order.

(2) The relevant assignee shall dispose of the radio equipment under sub-rule (1), using any method as the Central Government may specify on the portal and shall submit the document evidencing such disposal, in such form and manner, as the Central Government may specify thereon.

CHAPTER IV
MISCELLANEOUS

12. Powers of Central Government.—(1) The Central Government may specify on the portal the restrictions on use of spectrum by the assignee in restricted areas falling near the international borders of the territory of India, the Line of Control, the Line of Actual Control of India, or any other area as the Central Government may specify on the portal.

(2) The Central Government may, for the purpose of giving effect to these rules, issue orders, directions or guidelines not inconsistent with the Act or these rules, which shall constitute the terms and conditions applicable to every assignee.

(3) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, amend the Schedules to these rules.

13. Breach.—(1) A breach of terms and conditions under these rules by an assignee shall constitute a breach as referred to in section 32 of the Act.

(2) The Central Government may, after due consideration of the recommendations received under clause (b) of sub-section (1) of section 32 of the Act and giving an opportunity of being heard to the assignee, issue an order of suspension, revocation or curtailment of spectrum assignment under sub-section (2) of section 32 of the Act.

(3) Every order under sub-rule (2) shall be published by the Central Government on the portal, and be effective immediately from the date of publishing of such order:

Provided that the suspension of assignment, authorisation or licence shall not be a cause or ground for extension of the duration of the assignment.

(4) The assignee shall not be entitled to refund of fees or any other charges paid in respect of an assignment which is the subject matter of suspension, revocation, curtailment, modification or variation.

14. Digital implementation.—The Central Government may, in furtherance of section 53 of the Act, notify one or more portals for the digital implementation of these rules, including publication of any form, manner, order, direction or guideline to be specified under these rules.

SCHEDULE I

(See rules 3(2) and 4)

Persons eligible to apply for spectrum assignment	Specific usages	Applicable annexures on specific terms and conditions, including methodology for determination of spectrum charges
1. National security and defence		
Central Government or any agency designated by the Central Government for the purpose of entry 1 of the First Schedule to the Act.	(a) Land Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands, having bandwidth up to 375 kHz; (b) Maritime Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (c) Aeronautical Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (d) Radars for Radionavigation and Radiolocation Services; (e) Fixed and Mobile Services having Multiplexed Multi-channels; and (f) Satellite based Services.	(a) Annexure-II: Land Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands, having bandwidth up to 375 kHz; (b) Annexure-III: Maritime Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (c) Annexure-IV: Aeronautical Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (d) Annexure-V: Radars for Radionavigation and Radiolocation Services; (e) Annexure-VI: Fixed and Mobile Services having Multiplexed Multi-channels; (f) Annexure-VII: Satellite based Service; and (g) Annexure-XIII: Late charges for delayed payment of spectrum charges.
2. Law Enforcement and crime prevention		
(a) Central Government, State Government or any agency designated by such government for the purpose of entry 2 of the First Schedule to the Act; and (b) If the person specified in clause (a) seeks spectrum assignment for captive mobile radio trunking network, such person shall also hold a captive mobile radio trunking service authorisation under the Telecommunications (Authorisation for Captive Telecommunication Services) Rules, 2026.	(a) Land Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands, having bandwidth up to 375 kHz; (b) Maritime Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (c) Aeronautical Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (d) Radars for Radionavigation and Radiolocation Services; (e) Fixed and Mobile Services having Multiplexed Multi-channels; and (f) Satellite based Services.	(a) Annexure-II: Land Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands, having bandwidth up to 375 kHz; (b) Annexure-III: Maritime Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (c) Annexure-IV: Aeronautical Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (d) Annexure-V: Radars for Radionavigation and Radiolocation Services; (e) Annexure-VI: Fixed and Mobile Services having Multiplexed Multi-channels; (f) Annexure-VII: Satellite based Services; and (g) Annexure-XIII: Late charges for delayed payment of spectrum charges.
3. Public broadcasting services		
Any person holding the relevant authorisation or licence, as the Central Government may specify on the portal.	Terrestrial Broadcasting Service	(a) Annexure-I: Terrestrial Broadcasting Service; and

Persons eligible to apply for spectrum assignment	Specific usages	Applicable annexures on specific terms and conditions, including methodology for determination of spectrum charges
		(b) Annexure-XIII: Late charges for delayed payment of spectrum charges.
4. Disaster Management, safeguarding life and property		
(a) Central Government, State Government or any agency designated by such government for the purpose of entry 4 of the First Schedule to the Act; (b) A statutory body established under a law made by Parliament or by the Legislature of a State, having powers to undertake activities for the purpose of entry 4 of the First Schedule to the Act; (c) Any person, other than as specified under clauses (a) and (b), who satisfies the criteria specified under sub-rule (2) of rule 4; and (d) If the person specified in clauses (a) to (c) seeks spectrum assignment for captive mobile radio trunking network, such person shall also hold a captive mobile radio trunking service authorisation under the Telecommunications (Authorisation for Captive Telecommunication Services) Rules, 2026.	(a) Land Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands, having bandwidth up to 375 kHz; (b) Maritime Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (c) Aeronautical Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (d) Radars for Radionavigation and Radiolocation Services; (e) Fixed and Mobile Services having Multiplexed Multi-channels; and (f) Satellite based Services.	(a) Annexure-II: Land Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands, having bandwidth up to 375 kHz; (b) Annexure-III: Maritime Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (c) Annexure-IV: Aeronautical Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands (d) Annexure-V: Radars for Radionavigation and Radiolocation Services; (e) Annexure-VI: Fixed and Mobile Services having Multiplexed Multi-channels; (f) Annexure-VII: Satellite based Services; and (g) Annexure-XIII: Late charges for delayed payment of spectrum charges.
Any person holding authorisation to provide access services as well as spectrum assignment for access spectrum, in accordance with applicable law, may seek spectrum assignment in respect of entry 4 of this Scheduel, for a duration not exceeding three months.	Usages shall be as may be specified by the Central Government on the portal.	Annexure-XI: Spectrum Charges for Access Spectrum.
5. Promoting scientific research, resource development and exploration		
(a) Central Government, State Government or any agency designated by such Government for the purpose of entry 5 of the First Schedule to the Act; (b) A statutory body established under a law made by Parliament or by the	(a) Land Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands, having bandwidth up to 375 kHz; (b) Maritime Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands;	(a) Annexure-II: Land Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands, having bandwidth up to 375 kHz; (b) Annexure-III: Maritime Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands (c) Annexure-IV: Aeronautical Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands;

Persons eligible to apply for spectrum assignment	Specific usages	Applicable annexures on specific terms and conditions, including methodology for determination of spectrum charges
Legislature of a State, having powers to undertake activities for the purpose of entry 5 of the First Schedule to the Act; and (c) Any person, other than as specified under clauses (a) and (b), who satisfies the criteria specified under sub-rule (2) of rule 4.	(c) Aeronautical Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (d) Radars for Radionavigation and Radiolocation Services; (e) Fixed and Mobile Services having Multiplexed Multi-channels; and (f) Satellite based Services.	(d) Annexure-V: Radars for Radionavigation and Radiolocation Services; (e) Annexure-VI: Fixed and Mobile Services having Multiplexed Multi-channels; (f) Annexure-VII: Satellite based Services; and (g) Annexure-XIII: Late charges for delayed payment of spectrum charges.
6. Safety and operation of roads, railways, metro, regional rail, inland waterways, airports, ports, pipelines, shipping, and other transport systems		
(a) Central Government, State Government or any agency designated by such government for the purpose of entry 6 of the First Schedule to the Act; (b) A statutory body established under a law made by Parliament or by the Legislature of a State, having powers to undertake activities for the purpose of entry 6 of the First Schedule to the Act; (c) Any person, other than as specified under clauses (a) and (b), who satisfies the criteria specified under sub-rule (2) of rule 4; (d) If the person specified in clauses (a) to (c), seeks spectrum assignment for captive mobile radio trunking network, such person shall also hold a captive mobile radio trunking service authorisation under the Telecommunications (Authorisation for Captive Telecommunication Services) Rules, 2026; and (e) The persons specified under clauses (a) to (c) shall also hold relevant permissions under applicable law relevant to the sector for which the assignment is sought.	(a) Land Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands, having bandwidth up to 375 kHz; (b) Maritime Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (c) Aeronautical Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (d) Radars for Radionavigation and Radiolocation Services; (e) Fixed and Mobile Services having Multiplexed Multi-channels; (f) Satellite based Services; and (g) Services in respect of safety and operations of metro and regional rail systems.	(a) Annexure-II: Land Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands, having bandwidth up to 375 kHz; (b) Annexure-III: Maritime Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (c) Annexure-IV: Aeronautical Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (d) Annexure-V: Radars for Radionavigation and Radiolocation Services; (e) Annexure-VI: Fixed and Mobile Services having Multiplexed Multi-channels; (f) Annexure-VII: Satellite based Services; (g) Annexure-XI: Spectrum Charges for Access Spectrum; and (h) Annexure-XIII: Late charges for delayed payment of spectrum charges.

Persons eligible to apply for spectrum assignment	Specific usages	Applicable annexures on specific terms and conditions, including methodology for determination of spectrum charges
7. Conservation of natural resources and wildlife		
(a) Central Government, State Government or any agency designated by such government for the purpose of entry 7 of the First Schedule to the Act; (b) A statutory body established under a law made by Parliament or by the Legislature of a State, having powers to undertake activities for the purpose of entry 7 of the First Schedule to the Act; and (c) Any person, other than as specified under clauses (a) and (b), who satisfies the criteria specified under sub-rule (2) of rule 4.	(a) Land Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands, having bandwidth up to 375 kHz; (b) Maritime Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (c) Aeronautical Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (d) Radars for Radionavigation and Radiolocation Services; (e) Fixed and Mobile Services having Multiplexed Multi-channels; and (f) Satellite based Services.	(a) Annexure-II: Land Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands, having bandwidth up to 375 kHz; (b) Annexure-III: Maritime Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (c) Annexure-IV: Aeronautical Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (d) Annexure-V: Radars for Radionavigation and Radiolocation Services; (e) Annexure-VI: Fixed and Mobile Services having Multiplexed Multi-channels; (f) Annexure-VII: Satellite based Services; and (g) Annexure-XIII: Late charges for delayed payment of spectrum charges.
8. Meteorological department and weather forecasting		
(a) Central Government, State Government or any agency designated by such government for the purpose of entry 8 of the First Schedule to the Act; (b) A statutory body established under a law made by Parliament or by the Legislature of a State, having powers to undertake activities for the purpose of entry 8 of the First Schedule to the Act; and (c) Any person, other than as specified under clauses (a) and (b), who satisfies the criteria specified under sub-rule (2) of rule 4.	(a) Land Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands, having bandwidth up to 375 kHz; (b) Radars for Radionavigation and Radiolocation Services; (c) Fixed and Mobile Services having Multiplexed Multi-channels; and (d) Satellite based Services.	(a) Annexure-II: Land Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands, having bandwidth up to 375 kHz; (b) Annexure-V: Radars for Radionavigation and Radiolocation Services; (c) Annexure-VI: Fixed and Mobile Services having Multiplexed Multi-channels; (d) Annexure-VII: Satellite based Services; and (e) Annexure-XIII: Late charges for delayed payment of spectrum charges.
9. Internationally recognised dedicated bands for amateur stations, navigation, telemetry, and other like usages		
(a) Central Government, State Government or any agency designated by such government for the purpose of entry 9 of the First Schedule to the Act; (b) A statutory body established under a law made by Parliament or by the Legislature of a State, having powers to undertake activities for the purpose of	(a) Land Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands, having bandwidth up to 375 kHz; (b) Maritime Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (c) Aeronautical Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands;	(a) Annexure-II: Land Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands, having bandwidth up to 375 kHz; (b) Annexure-III: Maritime Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (c) Annexure-IV: Aeronautical Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands;

Persons eligible to apply for spectrum assignment	Specific usages	Applicable annexures on specific terms and conditions, including methodology for determination of spectrum charges
entry 9 of the First Schedule to the Act; and (c) Any person, other than as specified under clauses (a) and (b), who satisfies the criteria specified under sub-rule (2) of rule 4.	(d) Radars for Radionavigation and Radiolocation Services; (e) Fixed and Mobile Services having Multiplexed Multi-channels; and (f) Satellite based Services.	(d) Annexure-V: Radars for Radionavigation and Radiolocation Services; (e) Annexure-VI: Fixed and Mobile Services having Multiplexed Multi-channels; (f) Annexure-VII: Satellite based Services; and (g) Annexure-XIII: Late charges for delayed payment of spectrum charges
10. Use by Central Government, State Government, or their entities or other authorised entities for safety and operations of mines, ports and oil exploration and such other activities where the use of spectrum is primarily for supporting the safety and operations		
(a) Central Government, State Government or any agency designated by such government for the purpose of entry 10 of the First Schedule to the Act; (b) A statutory body established under a law made by Parliament or by the Legislature of a State, having powers to undertake activities for the purpose of entry 10 of the First Schedule to the Act; (c) Any person, other than as specified under clauses (a) and (b), who satisfies the criteria specified under sub-rule (2) of rule 4; (d) If the persons specified in clauses (a) to (c) seek spectrum assignment for captive mobile radio trunking network, such person shall also hold a captive mobile radio trunking service authorisation under the Telecommunications (Authorisation for Captive Telecommunication Services) Rules, 2026; and (e) The persons specified under clauses (a) to (c) shall also hold relevant permissions under applicable law relevant to the sector for which the assignment is sought.	(a) Land Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands, having bandwidth up to 375 kHz; (b) Maritime Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (c) Aeronautical Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (d) Radars for Radionavigation and Radiolocation Services; (e) Fixed and Mobile Services having Multiplexed Multi-channels; and (f) Satellite based Services.	(a) Annexure-II: Land Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands, having bandwidth up to 375 kHz; (b) Annexure-III: Maritime Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (c) Annexure-IV: Aeronautical Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (d) Annexure-V: Radars for Radionavigation and Radiolocation Services; (e) Annexure-VI: Fixed and Mobile Services having Multiplexed Multi-channels; (f) Annexure-VII: Satellite based Services; and (g) Annexure-XIII: Late charges for delayed payment of spectrum charges.

Persons eligible to apply for spectrum assignment	Specific usages	Applicable annexures on specific terms and conditions, including methodology for determination of spectrum charges
11. Public Mobile Radio Trunking Services		
(a) Central Government, State Government or any agency designated by such government for the purpose of entry 11 of the First Schedule to the Act; (b) A statutory body established under a law made by Parliament or by the Legislature of a State, having powers to undertake activities for the purpose of entry 11 of the First Schedule to the Act; and (c) Any person holding the relevant authorisation or licence, as the Central Government may specify on the portal.	PMRT Service	(a) Annexure-VIII: PMRT Service; and (b) Annexure-XIII: Late charges for delayed payment of spectrum charges.
12. Radio backhaul for telecommunications services		
The following entities holding spectrum in the range of frequencies specified by the Central Government on the portal: (a) Central Government, State Government or any agency designated by such government for the purpose of entry 12 of the First Schedule to the Act; (b) Any statutory body established under a law made by Parliament or by the Legislature of a State, having powers to undertake activities for the purpose of entry 12 of the First Schedule to the Act; and (c) Any person holding the relevant authorisation or licence, as the Central Government may specify on the portal.	Radio Backhaul	Annexure-X: Radio Backhaul.
13. Community Radio Stations		
Any person holding the relevant authorisation or licence, as the Central Government may specify on the portal.	Terrestrial Broadcasting Service	(a) Annexure-I: Terrestrial Broadcasting Service; and (b) Annexure-XIII: Late charges for delayed payment of spectrum charges.
14. In-flight and maritime connectivity		
(a) Central Government, State Government or any agency designated by such government	In-flight and maritime connectivity	No spectrum charge shall be applicable.

Persons eligible to apply for spectrum assignment	Specific usages	Applicable annexures on specific terms and conditions, including methodology for determination of spectrum charges
for the purpose of entry 14 of the First Schedule to the Act; (b) A statutory body established under a law made by Parliament or by the Legislature of a State, having powers to undertake activities for the purpose of entry 14 of the First Schedule to the Act; and (c) Any person holding the relevant authorisation or licence, as the Central Government may specify on the portal.		
15. Space research and application, launch vehicle operations and ground station for satellite control		
(a) Central Government, State Government or any agency designated by such government for the purpose of entry 15 of the First Schedule to the Act; (b) A statutory body established under a law made by Parliament or by the Legislature of a State, having powers to undertake activities for the purpose of entry 15 of the First Schedule to the Act; and (c) Any person, other than as specified under clauses (a) and (b), who satisfies the criteria specified under sub-rule (2) of rule 4.	Satellite based Services	(a) Annexure-VII: Satellite based Services; and (b) Annexure-XIII: Late charges for delayed payment of spectrum charges.
16. Certain satellite-based services listed below:		
16(a). Teleports		
Any person holding the relevant authorisation or licence, as the Central Government may specify on the portal.	Satellite based Services	(a) Annexure-VII: Satellite based Services; and (b) Annexure-XIII: Late charges for delayed payment of spectrum charges.
16(b). Television channels		
Any person holding the relevant authorisation or licence, as the Central Government may specify on the portal.	Satellite based Services	(a) Annexure-VII: Satellite based Services; and (b) Annexure-XIII: Late charges for delayed payment of spectrum charges.
16(c). Direct To Home		
Any person holding the relevant authorisation or licence, as the Central Government may specify on the portal.	Satellite based Services	(a) Annexure-VII: Satellite based Services; and (b) Annexure-XIII: Late charges for delayed payment of spectrum charges.

Persons eligible to apply for spectrum assignment	Specific usages	Applicable annexures on specific terms and conditions, including methodology for determination of spectrum charges
16(d). Headend In The Sky		
Any person holding the relevant authorisation or licence, as the Central Government may specify on the portal.	Satellite based Services	(a) Annexure-VII: Satellite based Services; and (b) Annexure-XIII: Late charges for delayed payment of spectrum charges.
16(e). Digital Satellite News Gathering		
Any person holding the relevant authorisation or licence, as the Central Government may specify on the portal.	Satellite based Services	(a) Annexure-VII: Satellite based Services; and (b) Annexure-XIII: Late charges for delayed payment of spectrum charges.
16(f)(1). Very Small Aperture Terminal (Captive)		
(a) Central Government, State Government or any agency designated by such government for the purpose of entry 16 of the First Schedule to the Act in respect of Very Small Aperture Terminal (Captive); (b) A statutory body established under a law made by Parliament or by the Legislature of a State, having powers to undertake activities for the purpose of entry 16 of the First Schedule to the Act in respect of Very Small Aperture Terminal (Captive); and (c) Any person holding the relevant authorisation or licence, as the Central Government may specify on the portal.	Satellite based Services using Geo-Stationary Orbit	(a) Annexure-VII: Satellite based Services; and (b) Annexure-XIII: Late charges for delayed payment of spectrum charges.
16(f)(2). Very Small Aperture Terminal (Commercial)		
(a) Central Government, State Government or any agency designated by such government for the purpose of entry 16 of the First Schedule to the Act in respect of Very Small Aperture Terminal (Commercial); authorised by the Central Government, (b) A statutory body established under a law made by Parliament or by the Legislature of a State, having powers to undertake activities for the purpose of entry 16 of the First Schedule to the Act in	Satellite-based Commercial Communication Services using Geo-Stationary Orbit	Annexure-IX: Satellite-based Commercial Communication Services.

Persons eligible to apply for spectrum assignment	Specific usages	Applicable annexures on specific terms and conditions, including methodology for determination of spectrum charges
respect of Very Small Aperture Terminal (Commercial); and (c) Any person holding the relevant authorisation or licence, as the Central Government may specify on the portal.		
16(g). National Long Distance		
(a) Central Government, State Government or any agency designated by such government for the purpose of entry 16 of the First Schedule to the Act in respect of National Long Distance; (b) A statutory body established under a law made by Parliament or by the Legislature of a State, having powers to undertake activities for the purpose of entry 16 of the First Schedule to the Act in respect of National Long Distance; and (c) Any person holding the relevant authorisation or licence, as the Central Government may specify on the portal.	Satellite based Services	(a) Annexure-VII: Satellite based Services; and (b) Annexure-XIII: Late charges for delayed payment of spectrum charges.
16(h). International Long Distance		
(a) Central Government, State Government or any agency designated by such government for the purpose of entry 16 of the First Schedule to the Act in respect of International Long Distance; (b) A statutory body established under a law made by Parliament or by the Legislature of a State, having powers to undertake activities for the purpose of entry 16 of the First Schedule to the Act in respect of International Long Distance; and (c) Any person holding the relevant authorisation or licence, as the Central	Satellite based Services	(a) Annexure-VII: Satellite based Services; and (b) Annexure-XIII: Late charges for delayed payment of spectrum charges.

Persons eligible to apply for spectrum assignment	Specific usages	Applicable annexures on specific terms and conditions, including methodology for determination of spectrum charges
Government may specify on the portal.		
16(i). Mobile Satellite Service Bands specified in the First Schedule to the Act		
Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) under the sui generis category.	Global Satellite Phone Service (GSPS) by Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) under the sui generis category.	Annexure-IX: Satellite-based Commercial Communication Services.
17. Use by Central Government, State Government or their authorised agencies for telecommunication services		
(a) Central Government, State Government or any agency designated by such government for the purpose of entry 17 of the First Schedule to the Act; (b) If the person specified in clause (a) seeks spectrum assignment for captive mobile radio trunking network, such person shall also hold a captive mobile radio trunking service authorisation under the Telecommunications (Authorisation for Captive Telecommunication Services) Rules, 2026.	(a) Land Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands, having bandwidth up to 375 kHz; (b) Maritime Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (c) Aeronautical Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (d) Radars for Radionavigation and Radiolocation Services; (e) Fixed and Mobile Services having Multiplexed Multi-channels; and (f) Satellite based Services.	(a) Annexure-II: Land Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands, having bandwidth up to 375 kHz; (b) Annexure-III: Maritime Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (c) Annexure-IV: Aeronautical Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands; (d) Annexure-V: Radars for Radionavigation and Radiolocation Services; (e) Annexure-VI: Fixed and Mobile Services having Multiplexed Multi-channels; (f) Annexure-VII: Satellite based Services; and (g) Annexure-XIII: Late charges for delayed payment of spectrum charges
18. Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) and Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL)		
(a) Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL); and (b) Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL), who shall hold the relevant authorisation or licence, as the Central Government may specify on the portal.		Annexure-XI: Spectrum Charges for Access Spectrum.
19. Testing, Trial, experimental, demonstration purposes for enabling implementation of new technologies, including for creation of one or more Regulatory Sandboxes		
(a) Central Government, State Government or any agency designated by such government for the purpose of entry 19 of the First Schedule to the Act; (b) A statutory body established under a law made by Parliament or by the Legislature of a State, having powers to undertake activities for the purpose of entry 19 of	Testing, trial, experimental, demonstration purposes for enabling implementation of new technologies, including for creation of one or more Regulatory Sandboxes.	Annexure-XII: Testing, trial, experimental, demonstration purposes for enabling implementation of new technologies, including for creation of one or more Regulatory Sandboxes.

Persons eligible to apply for spectrum assignment	Specific usages	Applicable annexures on specific terms and conditions, including methodology for determination of spectrum charges
the First Schedule to the Act; and (c) Any person holding the relevant authorisation or licence, as the Central Government may specify on the portal.		

SCHEDULE II

(See rules 3(2) and 6(2))

Annexure-I- Terrestrial Broadcasting Service

1. This annexure shall apply to assignment of spectrum for Terrestrial Broadcasting Service (including public broadcasting services and community radio broadcasting services) in respect of entries 3 and 13 of Schedule I.

2. This annexure comprises of the following:
   (a) Tables A1 and A2 specifying the annual spectrum fees; and
   (b) Table B specifying the radio station and radio equipment fees.

Table A1: Annual spectrum fees

Type of Broadcasting	Power delivered to antenna	Annual spectrum fees (in Rs) per radio station
Public Broadcasting Services by Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) established under the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990)	**Sound:**	
	Low Power FM (Up to 100 W)	30,000
	Medium Power FM (0.1 KW-1KW)	60,000
	High Power FM (1KW-3KW)	1,25,000
	AM/MW Broadcasting	50,000
	Television:	
	Low Power TV (Up to 1KW)	VHF: 1,20,000 UHF: 3,60,000
	High Power TV (Above 1KW)	VHF: 1,20,000 UHF: 3,50,000
Public Broadcasting Services by any entity other than Prasar Bharti	FM stations	3,37,500
Community Radio Broadcasting	Low power FM (Up to 50 W)	22,500 No separate permission shall be required, and no fees are payable for a standby radio station for community radio broadcasting.

Table A2: Spectrum fees for low power indoor radio equipment

Spectrum fees (in Rs.)	5,000 per radio equipment, for the lifetime of the equipment.

Table B: Radio station / Radio equipment fees

S. No.	Type of radio station / Radio equipment (including for standby sets)	Radio station / Radio equipment fees (in Rs.)
1.	Broadcast transmitter station	500 per radio station per annum
2.	Low power indoor radio equipment: *Provided that* such equipment shall not be used for outdoor events including social, cultural and religious events or events held in open-air stadiums.	250 per radio equipment, for the lifetime of the equipment.
3.	Hot standby equipment	Nil

Annexure-II: Land Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands, having bandwidth up to 375 kHz

1. This annexure shall apply to assignment of spectrum for Land Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands, having bandwidth up to 375 kHz in respect of entries 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 17 of Schedule I.

2. This annexure comprises of the following:
   (a) Table A1 read with Tables A2 and A3 specifying the annual spectrum fees for fixed-site networks, including:
      (i) small area applications such as industrial units, factories and municipalities; and
      (ii) one or more base stations, mobile stations, or any combinations thereof, where area of a district is small enough to be covered by four base or repeater stations;
   (b) Table B specifying the spectrum fees for UHF Short Range Radio (USR);
   (c) Table C specifying the annual spectrum fees for Area-based Operation in VHF/UHF band for Land Mobile Stations, including telecommunication network having coverage beyond the fixed-site category, where area users are those which operate over larger area of operations such as:
      (i) Pan-India users, like: Indian Railways, Defence, Central Paramilitary Forces (CPMFs), oil marketing companies and airports authority;
      (ii) State-wide users, such as: state police organizations, disaster management authorities, state forest departments, electricity boards and water resources departments;
      (iii) District-wide users, such as: public transport, district authorities; and
      (iv) Base stations, mobile stations, and any combination thereof;
   (d) Table D specifying the annual spectrum fees for Land Mobile Service in LF/MF/HF bands per 3 kHz bandwidth; and
   (e) Table E specifying the annual radio station fees applicable to Annexure II.
   (f) Table F specifying the radio equipment fees applicable to equipment that blocks telecommunication.

3. In order to promote efficient use of radio frequencies in respect of assignment of spectrum under this annexure, the following provisions shall apply:
   (a) The letter of intent issued under rule 5 and spectrum assignment letter issued under rule sub-rule (3) of rule 5, shall specify the frequency range of operation limited to a maximum extent of 10 simplex frequencies or 2 duplex frequencies.
   (b) An assignee may subsequently, based on its requirements, request for additional frequencies, by submitting an application in the form as specified on the portal, along with justification for the same.
   (c) Any grant of additional frequencies by the Central Government shall be recorded as a modification of the spectrum assignment letter.

4. The following conditions shall apply for levy of spectrum fees in respect of assignment of spectrum under this annexure:
   (a) The spectrum fees for LF/MF/HF/VHF bands shall be levied for channel bandwidth and not for the occupied bandwidth.
   (b) The spectrum fees as specified in Table A1 shall be subject to the following conditions:
      (i) Half of the fees specified in Table A1 shall apply for bandwidths of 6.25 kHz or less, and for bandwidths greater than 12.5 kHz, the spectrum fees shall be charged in multiples of 12.5 kHz, and any fractional bandwidth shall be rounded up to the next multiple of 12.5 kHz.
      (ii) In case of a telecommunication network spread across population categories across two locations, i.e., different class of cities, the charging of higher population category shall be applicable.

(iii) Annual spectrum fees for frequency assignments that are in the sea (offshore), sub-surface use, such as, tunnel-radio, shall be charged at the minimum charging rate, in the respective band and population category.

(iv) If antenna of radio equipment is used indoors or underground or is a down-fire, leaky feeder or radiating cable type, it will fall within Category 1 of the respective band and population category.

(v) Annual spectrum fees in Table A1 shall be applicable for the first 10 simplex frequencies or 2 duplex frequencies.

(vi) Beyond the quantity of frequencies, an incremental additional charge of 30% higher for the next 5 simplex frequencies or 2 duplex frequencies, and 50% higher charges on number of frequencies exceeding beyond 15 simplex or 4 duplex frequencies shall be applicable.

(vii) No spectrum fee shall be applicable for equipment that blocks telecommunication.

Tables A1, A2, A3 for annual spectrum fees for fixed-site networks

Table A1: Annual spectrum fees for fixed-site networks in VHF/ UHF band per 12.5 kHz bandwidth

Band category[1]	**Annual spectrum fees (in Rs.) for Highly Popular Bands (HPB)**			**Annual spectrum fees (in Rs.) for Medium Popular Bands (MPB)**			**Annual spectrum fees (in Rs.) for Less Popular Bands (LPB)**
Coverage Category[2]	1	2	3	1	2	3	1,2 or 3
Population category* A+	15,000	45,000	75,000	12,000	36,000	45,000	3,000
Population category* A	10,000	25,000	40,000	8,000	24,000	36,000	
Population category* B	7,500	15,000	25,000	5,000	12,000	20,000	
Population category* C	5,000	10,000	15,000	3,750	7,000	15,000	
All others	3,000	5,000	8,000	3,000	4,000	5,000	

[1]Refer to Table-A2.

[2]Refer to Table-A3.

* Population categories shall be as determined by the Central Government.

Table A2: Highly/ Medium/Less Popular bands

Band categories	**Bands**	**Frequency range (MHz)**
Highly Popular bands (HPB)	VHF	137 –174
	UHF-I	410 – 430
	UHF-II	430 –470
Medium Popular bands (MPB)	UHF-III	380 – 400 800 MHz for CMRTS (except for IMT band)
Less Popular bands (LPB)	Any other band other than above	

Table A3: Coverage Category

Coverage categories	Combinations of Effective Radiated Power (ERP) in Watts (P), and antenna height above ground level (Ah)in meters – for base station(s)	Possible operational area - Radius (R) in km
Category 1	P ≤5W and Ah ≤10m	0 < R ≤3
Category 2	P ≤5W and 10m < Ah ≤30m	3 < R ≤15
	P> 5W and Ah ≤10m	
Category 3	P> 5W and Ah > 10m	15 < R ≤30
	P ≤5W and Ah > 30m	

Table B: Spectrum fees for UHF Short Range Radio (USR)

Spectrum fees (in Rs.)	15,000 per frequency spot, for 5 years

Table C: Annual spectrum fees for Area-based Operation in VHF/UHF band for Land Mobile Stations

Area	Annual spectrum fees (in Rs.) for Highly Popular bands	Annual spectrum fees (in Rs.) for Medium Popular bands	Annual spectrum fees (in Rs.) for Less Popular bands
Pan India	50,00,000	37,50,000	25,00,000
State-wide Category-A[1]	5,00,000	3,75,000	2,50,000
State-wide Category -B[2]	3,00,000	2,25,000	1,50,000
District-wide	5 x fixed-site Coverage Category-3 (as per Table A3)	5 x fixed-site Coverage Category-3 (as per Table A3)	5 x fixed-site Coverage Category-3 (as per Table A3)

[1]*State-wide Category-A: Delhi, Maharashtra, West Bengal, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Telangana, Haryana, Kerala, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Himachal Pradesh, and Orrisa.*

[2]*State-wide Category-B: Uttarakhand, Sikkim, Goa, Meghalaya, Tripura, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, and Mizoram and Union Territories.*

Table D: Annual spectrum fees for Land Mobile Service in LF/MF/HF bands per 3 kHz bandwidth

Frequency bands	Annual spectrum fees (in Rs.) per annum per spot (irrespective of number of sets)
HF (3 – 30 MHz)	1,00,000
MF (300 kHz – 3 MHz)	50,000
LF (9 kHz – 300 kHz)	50,000

Table E: Annual radio station fees applicable for Annexure II

S. No.	Type of radio station	Annual radio station fees (in Rs.)
1.	Base/ Fixed radio station	500 per radio station
2.	Vehicle /Handheld Mobile radio station	250 per radio station

Table F: radio equipment fees for the equipment that blocks telecommunication

S. No.	Type of equipment	radio equipment fees (in Rs.) for lifetime
1.	Fixed	500 per equipment
2.	Mobile (Vehicle /Handheld/places such as examination centre)	250 per equipment

Annexure-III: Maritime Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands

1. This annexure shall apply to assignment of spectrum for Maritime Mobile Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands (including port operation service and ship movement service as defined in NFAP) in respect of entries 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 and 17 of Schedule I.

2. This annexure comprises of:

   (a) Table A specifying the annual spectrum fees; and
   (b) Table B specifying the annual radio station fees.

3. Assignment of spectrum under this annexure shall be subject to the following conditions:

   (a) Frequency assignments to any person other than a public entity shall be made on a non-exclusive basis.

   (b) Public entities that are engaged in Ports and Search and Rescue (SAR) shall be assigned the requested number of frequencies on an exclusive basis.

   (c) Annual spectrum fees for LF/MF/HF/VHF bands and which exceed 30 MHz, shall be levied for the channel bandwidth and not for the occupied bandwidth.

   (d) The transmitting frequencies in the VHF maritime mobile band will be in accordance with Appendix 18 of Radio Regulation of ITU-R, as may be updated from time to time.

   (e) In the frequency band VHF (AIS/ATON[2]), there will be a minimum assignment of two frequencies.

4. The spectrum charges shall not be applicable for frequencies as determined by the Central Government in respect of: (a) Distress Urgency and Safety Communications, and (b) Inter-Ship Safety Communications.

Table A: Annual spectrum fees

In the table below, annual spectrum fees specified in respect of:

1. VHF/ UHF band is per 12.5 kHz bandwidth, and, for frequency bandwidth of 6.25 kHz or less, half of the fees specified shall apply;
2. VHF/ UHF bands having bandwidths greater than 12.5 kHz, shall be charged in multiples of 12.5 kHz, and any fractional bandwidth shall be rounded up to the next multiple of 12.5 kHz; and
3. LF/MF/HF bands is per 3 kHz bandwidth.

Frequency Bands	Annual spectrum fee (in Rs.) (irrespective of the number of sets of radio equipment)
VHF (Except AIS[1])/ UHF	20,000
VHF (AIS/ATON[2])	20,000, for two frequencies
HF (3 – 30 MHz)	1,00,000
MF (300 kHz – 3 MHz)	50,000
LF (9 kHz – 300 kHz)	50,000

[1]*AIS: Automatic Identification System*
[2]*ATON: AIS to Aid to Navigation (Physical/Virtual/Synthetic)*

Table B: Annual radio station fee

S. No.	Type of radio station	Annual radio station Fee (in Rs.)
1.	Coast station	500 per radio station
2.	Vehicle /Handheld radio station	250 per radio station
3.	Fishing trawlers	500 per trawler
4.	Ship stations	5000 per ship

Annexure-IV: Aeronautical Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands

1. This annexure shall apply to assignment of spectrum for Aeronautical Service in LF/MF/HF/VHF/UHF bands in respect of entries 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 and 17 of Schedule I.

2. Aeronautical Service shall include aeronautical mobile (route) service, aeronautical mobile (off-route) service, and aeronautical radio navigation service, as defined in the NFAP.

3. This annexure comprises of:
   (a) Table A specifying the annual spectrum fees; and
   (b) Table B specifying the radio station fees.

4. For the purpose of this annexure –
   (a) "Aeronautical Mobile Service" or "AMS" means a mobile service between aeronautical stations and aircraft stations, or between aircraft stations, in which survival craft stations may participate; emergency position-indicating radiobeacon stations may also participate in this service on designated distress and emergency frequencies;
   (b) "Aeronautical Radionavigation Service" or "ARNS" means a radionavigation service intended for the benefit and for the safe operation of aircraft.

5. Assignment of spectrum under this annexure shall be based on the following conditions:
   (a) Frequency assignments in respect of this annexure shall be made on an exclusive basis.

   (b) Annual spectrum fees for LF/MF/HF/VHF/UHF bands and which exceed 30 MHz, shall be levied for the channel bandwidth and not for the occupied bandwidth.

   (c) The spectrum charges shall not be applicable for frequencies as determined by the Central Government in respect of Distress Urgency and Safety Communications.

Table A: Annual spectrum fees

In the table below, annual spectrum fees specified in respect of:

1. VHF/ UHF band is per 12.5 kHz bandwidth, and, for bandwidth of 6.25 kHz or less, half of the fees specified shall apply;
2. VHF/ UHF bands having bandwidths greater than 12.5 kHz, shall be charged in multiples of 12.5 kHz, and any fractional bandwidth shall be rounded up to the next multiple of 12.5 kHz; and
3. LF/MF/HF bands is per 3 kHz bandwidth.

Frequency Bands	**Annual spectrum fees (in Rs.) per location (irrespective of the number of sets of radio equipment)**
VHF / UHF (ARNS /AMS)*	2,00,000 (For Tower and Approach) 75,000 (For Ground)
HF (3 – 30 MHz)	1,00,000
MF (300 kHz – 3 MHz)	50,000
LF(9 kHz – 300 kHz) (Radio Beacons)	50,000

***ARNS**: Aeronautical Radionavigation services such as ILS (Instrument Landing System), VOR (VHF Omni-directional Range), NDB (Non Directional Beacon)

***AMS**: Aeronautical Mobile Service (Route/off-Route)

Table B: Annual radio station fee

S. No.	Type of radio station	Annual radio station Fee (in Rs.)
1.	Fixed radio station	500 per radio station
2.	Vehicle /Handheld Mobile radio station	250 per radio station
3.	Aircraft stations	5000 per aircraft

Annexure-V: Radars for Radionavigation and Radiolocation Services

1. This annexure shall apply to assignment of spectrum for radars for radionavigation and radiolocation services in respect of entries 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 17 of Schedule I.

2. This annexure comprises of:
   (a) Table A read with Table C specifying the annual spectrum fees for high power radar (EIRP ≥ 10W) including ARNS (for bandwidth > 375 kHz), and wind profiler radars;
   (b) Table B read with Table C specifying the spectrum fees for low power radars (EIRP<10W); and
   (c) Table D specifying the radio station fees.

3. The following condition shall apply to assignment of spectrum under this annexure:
   (a) The frequency band for Table A and Table B shall be determined based on the necessary bandwidth, in the manner specified in Table C; and
   (b) The spectrum fees under Table A and Table B shall be calculated based on the necessary bandwidth (20 dB bandwidth) as specified in Table C and shall be independent of the coverage distance.

Table A: Annual spectrum fees

Type of radio station	Frequency Bands	Annual spectrum fees (in Rs.) per 100 kHz
High power radar (EIRP>=10W) including ARNS(for bandwidth > 375 kHz)	Upto 2690 MHz	12,000
	2690 -5000 MHz	
	5000-8500 MHz	3,000
	8500 -14500 MHz	1,200
	More than 14500 MHz	
Wind profiler radars	Upto 2690 MHz	4,000
	2690 -5000 MHz	
	5000-8500 MHz	1,000
	8500 -14500 MHz	400
	More than 14500 MHz	

Table B: Spectrum fees for Low power radars (EIRP<10W)

Type of radio station	Frequency Bands	Spectrum fees (in Rs.) per 100 kHz (applicable for 10 years)
Low power radars (EIRP<10W)	Upto 2690 MHz	1,200
	2690 -5000 MHz	
	5000-8500 MHz	300
	8500 -14500 MHz	120
	More than 14500 MHz	

Table C: Calculation of Necessary Bandwidth for radar application

1. The frequency band shall be determined based on the necessary bandwidth (20 dB Bandwidth) of the transmitted signal, where such technical details of the telecommunication equipment as submitted by an applicant under rule 4.
2. If such information is not contained in the technical details submitted under rule 4, the following formula shall be used:

(a) For a non-FM radar: $B_N = 1.79/\sqrt{t * tr}$ or $\frac{6.36}{t}$; whichever is less

(b) For FM pulse radar: $B_N = 1.79/\sqrt{t * tr} + 2B_c$

(c) For FM pulse radar (with frequency hopping): $B_N = 1.79/\sqrt{t * tr} + 2Bc$;

(d) For frequency hopping radars using non-FM pulses (including spread spectrum or coded pulses): $B_N = 1.79/\sqrt{t * tr} + B_s$;

(e) For FM/CW radars: $B_N = 2B_d$;

Where:

B_N = necessary bandwidth in MHz;

Bc = bandwidth of the frequency deviation (the total frequency shift during the pulse duration) in MHz;

B_d = bandwidth of the frequency deviation (peak difference between instantaneous frequency of the modulated wave and the carrier frequency for FM/CW radar systems) in MHz;

Bs = maximum range in MHz over which the carrier frequency will be shifted for a frequency hopping radar;

t = emitted pulse duration in μ sec at 50% amplitude (voltage) points. For coded pulses, the pulse duration is the interval between 50% amplitude points of one chip (sub-pulse). The 100% amplitude is the nominal flat top level of the pulse;

t_r = emitted pulse rise time in μ sec from the 10% to the 90% amplitude points on the leading edge. For coded pulse, it is the rise time of a sub-pulse; if the sub-pulse rise time is not discernible, assume it is 40% of the time to switch from one phase or sub-pulse to the next;

FM Radar = Frequency Modulated Radar;

CW Radar = Continuous Wave Radar.

Table D: Annual radio station fees

S. No.	Type of radio station (including standby sets)	Annual radio station fees (in Rs.)
1.	Radar station	1000 per radio station

Annexure-VI: Fixed and Mobile Services having Multiplexed Multi-channels

1. This annexure shall apply assignment of spectrum for Fixed and Mobile Services having Multiplexed Multi-channels in respect of entries 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 17 of Schedule I.

2. This annexure comprises of:
   (a) Table A specifying the formula for calculation of annual spectrum fees based on Tables A1 and A2; and
   (b) Table B specifying the radio station fees.

Table A: Formula for calculation of annual spectrum fees

The formula for calculation shall be as follows:

Annual spectrum fees (R) = MxCxW, where: M-factor (Coverage), C-factor (No. of frequency carriers) and W-factor (Bandwidth)

Table-A1: Rate of M-Factor

Distance Category	Maximum Distance (Km)	Value of M-Factor
I	≤ 2	750
II	> 2 ≤ 5	1500
III	> 5 ≤ 25	3000
IV	> 25 ≤ 60	6000
V	> 60 ≤ 120	11000
VI	> 120 ≤ 500	18750
VII	> 500	25000

Table-A2: Rate of W-Factor

Slabs of Adjacent Channel Separation (bandwidth) (in MHz) *(Any amount in fraction shall be rounded up to the next integer).*	Value of W-Factor
> 375 kHz ≤ 2 MHz	30
> 2 ≤ 3.5	40
> 3.5 ≤ 7	60
> 7 ≤ 14	90
> 14 ≤ 28	120
> 28 ≤ 56	150
> 56 ≤ 112	180
> 112 ≤ 256	210
> 256 ≤ 512	240
> 512	240 + 30 x (Excess bandwidth ⁄256, i.e., in steps of 256 MHz or part thereof)

Table B: Annual radio station fees

S. No.	Type of radio station	Annual radio station fees (in Rs.)
1.	Fixed radio station	1000 per radio station
2.	Vehicle Mobile/ Handheld Mobile radio station	250 per radio station

Annexure-VII: Satellite based Services

1. This annexure shall apply to assignment of spectrum for Satellite based Services (including Fixed Satellite Services (FSS), Broadcasting Satellite Services (BSS), Mobile Satellite Services (MSS) and Earth Exploration Satellite Services (EESS)/ Meteorological Satellite Service) in respect of entries 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16(a), 16(b), 16(c), 16(d), 16(e), 16(f)(1) (limited to captive VSAT), 16(g), 16(h) and 17 of Schedule I, and does not apply to Satellite-based Commercial Communication Services.

2. This annexure comprises of:
   (a) Part I read with Table 1 specifying the spectrum fees; and
   (b) Part II read with Table 2 specifying the radio station fees for earth stations operating under Satellite Services.

3. For the purpose of this annexure, "IoT" means internet of things, which comprises M2M communication over the internet.

Part I: Condition applicable to spectrum fees

1. The spectrum fees shall be payable on the total bandwidth assigned, including any guard bands, and in respect of frequencies transmitted from or into the territory of India.

2. For the purpose of calculation of spectrum fee in respect of Earth Exploration Satellite Service / Meteorological Satellite Service, only one remote terminal shall be taken into account, irrespective of the number of remote users or connections in the telecommunication network.

3. The spectrum fees in respect of Digital Satellite News Gathering (DSNG) /Satellite News Gathering (SNG), shall be payable for the frequencies used on both uplinks and downlinks.

4. In case the same frequency carrier is used from more than one DSNG van of the assignee, the following shall apply:
   (a) for the first DSNG van, the annual spectrum fees specified in this annexure shall be charged; and
   (b) for each additional DSNG van, spectrum fee at the rate of 25% of the annual spectrum fee specified in this annexure, shall be charged.

   Provided that, no spectrum fees shall be charged for such additional DSNG vans, deployed within the same venue.

5. Annual spectrum fees for Space Operation Services (TTC operation) shall be payable at the rate of Rs 1,50,000/- per earth station.

6. The spectrum fees shall not be applicable on remote terminals of data collection platforms, and IoT terminals used for providing location, and other data in MSS.

7. In all other cases not covered in points 1 to 5 above, spectrum fees shall be payable annually, calculated in accordance with the following formula:

   Annual spectrum fees (R) = Rs. 35000xBs, where Bs means the Bandwidth Factor calculated as provided under Table 1.

Table 1: Calculation of Bandwidth Factor (Bs)

S. No.	Total Assigned Bandwidth		Bandwidth Factor (Bs)			
			For uplink		For downlink	
			Broadcast*	Others	Broadcast*	Others
(i)	Up to and including 500 kHz (i.e., BW≤ 500 kHz)	Up to and including 100 kHz (i.e., BW ≤ 100 kHz)	0.25	0.20	Nil	0.20
(ii)		More than 100 kHz up to and including 250 kHz (i.e., 100 kHz < BW ≤ 250 kHz)	0.60	0.50	Nil	0.50
(iii)		More than 250 kHz up to and including 500 kHz (i.e., 250 kHz < BW ≤ 500 kHz)	1.25	1.00	Nil	1.00
(iv)	More than 500 kHz (i.e., BW > 500 kHz)		Total Bs			

*The term "Broadcast" as used in this table means transmission of television content through satellite, including through teleports, Digital Satellite News Gathering (DSNG) vans, Direct To Home (DTH), and Headend In The Sky (HITS).

The bandwidth factor shall be calculated as follows:

Total Bs = [Appropriate Bs from row (iii) above X bandwidth in number of multiple of 500 kHz] + [incremental Bs]

where,

i. Incremental Bs = [Appropriate Bs from row (i) above X number of multiple of 100KHz or part thereof in balance bandwidth]; and
ii. Balance bandwidth = remainder of [bandwidth/ 500 kHz]

Part II: Radio station fees for earth stations operating under Satellite based Services

1. The radio station fees for earth stations operating under Satellite based Services, other than for IoT or IoT devices in Aggregator or Direct-to-Satellite mode, shall be as provided in Table 2.

2. Radio station fees shall not be payable for IoT and IoT devices in Aggregator or Direct-to-Satellite mode.

Table 2: Annual radio station fees

S. No.	Type of earth station (including for standby sets)	Annual radio station fee (in Rs.)
1.	Fixed earth station/ Direct To Home (DTH)/ Teleport/ Digital Satellite News Gathering (DSNG)/ Long Distance (LD) /DCP/Infrastructure Providers-II (IP-II)	1000 per station
2.	Captive VSAT earth Station	500 per station
3.	Vehicle Mobile/ Handheld Mobile radio station	250 per radio station

Annexure-VIII: PMRT Service

1. This annexure shall apply to assignment of spectrum for Public Mobile Radio Trunking Services in respect of entry 11 of Schedule I.

2. This annexure comprises of:
   (a) Part A specifying the annual spectrum fees; and
   (b) Part B specifying the radio station fees.

PART A: Annual spectrum fees

The assignee shall pay annual spectrum fees by exercising one of the following options:

Option 1: Annual Payment of spectrum fees

1. Rs. 1200/- (Rupees One Thousand Two Hundred Only) per annum per 6.25 kHz channel for link distances up to 30 km in the city within the same service area.

2. Rs. 2400/- (Rupees Two Thousand Four Hundred Only) per annum per 6.25 kHz channel for link distances up to 60 km in the city within the same service area.

Option 2: One-Time Upfront Payment of spectrum fees

One-time upfront payment of spectrum fees for a period of five as follows:

1. Rs. 5,000 (Rupees Five Thousand Only) per 6.25 kHz channel for link distances up to 30 km in the city within the same service area.

2. Rs. 10,000 (Rupees Ten Thousand Only) per 6.25 kHz channel for link distances up to 60 km in the city within the same service area.

PART B: Radio station fees

The radio station fees shall be one percent of AGR, and shall be payable in accordance with the Telecommunications (Authorisation for provision of Miscellaneous Telecommunication Services) Rules, 2026.

Annexure IX: Satellite-based Commercial Communication Services

1. This annexure shall apply to assignment of spectrum for Satellite-based Commercial Communication Services in respect of entries 16(f)(2) (limited to VSAT Commercial) and 16(i) of Schedule I.

2. The spectrum charges shall be calculated as a percentage of adjusted gross revenue as provided below:

<table>
<tr><th>Type of satellite service</th><th colspan="2">Formula for calculation of annual spectrum charges</th></tr>
<tr><td rowspan="4">VSAT Commercial in Geo-Stationary Orbit</td><td>Range of user data rate</td><td>Spectrum charges</td></tr>
<tr><td>Up to 128 kbps</td><td>3.0% of AGR</td></tr>
<tr><td>Higher than 128 kbps and up to 512 kbps</td><td>3.5 % of AGR</td></tr>
<tr><td>Higher than 512 kbps and up to 2 Mbps</td><td>4.0 % of AGR</td></tr>
<tr><td>Global Satellite Phone Service (GSPS) by Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) under the sui generis category</td><td colspan="2">1% of AGR</td></tr>
</table>

Annexure-X: Radio Backhaul

1. This annexure shall apply to assignment of spectrum for Radio Backhaul in respect of entry 12 of Schedule I.

2. The spectrum charges shall be calculated cumulatively as a percentage of AGR as provided below:

Spectrum Bandwidth	Formula for calculation of spectrum charges calculated cumulatively and payable annually (% of AGR)
Microwave Access and Microwave backbone	
First carrier of 28 MHz (paired)	0.15%
Second carrier of 28 MHz (paired)	0.35%
Third carrier of 28 MHz (paired)	0.55%
Fourth carrier of 28 MHz (paired)	0.80%
Fifth carrier of 28 MHz (paired)	1.10%
Sixth carrier of 28 MHz (paired)	1.45%
Seventh carrier of 28 MHz (paired)	1.85%
Eighth carrier of 28 MHz (paired)	2.30%
Ninth carrier of 28 MHz (paired)	2.80%
Tenth carrier of 28 MHz (paired)	3.35%
Eleventh carrier of 28 MHz (paired)	3.95%
E Band	
First carrier of 250 MHz (paired)	0.15%
Second carrier of 250 MHz (paired)	0.30%

Annexure-XI: Spectrum Charges for Access Spectrum

1. This annexure shall apply to spectrum assignment for:
   (a) Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) and Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL) in respect of entry 18 of Schedule I;
   (b) a duration not exceeding three months in respect of entry 4 of Schedule I; and
   (c) safety and operations of metro and regional rail systems under entry 6 of Schedule I.

2. Assignment of access spectrum through administrative process, in the frequency bands or parts thereof as the Central Government may specify on the portal, as identified for implementation of International Mobile Telecommunication in the National Frequency Allocation Plan, shall be on the basis of market price.

Explanation—For the purposes of this Annexure, the expression "market price" shall mean the reserve price or the price of access spectrum, determined through auction held pursuant to the last NIA published prior to the effective date of spectrum assignment, whichever is higher:

Provided that where such auction was held more than twelve months prior to the effective date of spectrum assignment, such reserve price or price determined under the auction, as the case may be, shall be arrived at by using the relevant marginal cost of funds based lending rate (MCLR) of the State Bank of India as notified on the website of State Bank of India.

Annexure-XII: Testing, trial, experimental, demonstration purposes for enabling implementation of new technologies, including for creation of one or more Regulatory Sandboxes

1. This annexure shall apply to assignment of spectrum for testing, trial, experimental, demonstration purposes for enabling implementation of new technologies, including for creation of one or more Regulatory Sandboxes in respect of entry 19 of Schedule I.

2. The assignee shall, in respect of spectrum assignment under this annexure,—
   (a) ensure that any testing, trial, experimental, demonstration does not cause interference to any telecommunication equipment, telecommunication network or telecommunication service of any other authorised entity or assignee; and
   (b) not claim protection from interference caused by any telecommunication equipment, telecommunication network or telecommunication service of any other authorised entity or assignee.

   Explanation.—In this provision, the expression "interference" shall mean the effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction on reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation or loss of information that could have been extracted in the absence of such unwanted energy.

3. Any assignment of spectrum under this annexure shall be made on a non-interference and non-protection basis, and shall not be used for regular use or for providing telecommunication services to users.

4. The conditions as applicable to assignment of spectrum under this annexure are as follows:
   (a) Testing:
      (i) Testing means the temporary conduct of radio frequency tests of wireless telecommunication equipment or systems, including but not limited to product testing, compliance testing, performance testing, field testing, network testing, and regulatory testing, for the purpose of technical evaluation, validation, or certification, and not for commercial operation or delivery of telecommunication services.
      (ii) The assignment of spectrum in respect of testing shall be made for indoor and outdoor environment, in radiating mode, where EIRP is more than 100 mW.
      (iii) Testing in indoor and outdoor environment, in radiating mode, where EIRP is less than 100 mW, is exempt from the requirement of assignment of spectrum.
      (iv) The assignee undertaking testing shall ensure that the associated technologies, products, processes or business models undergoing testing, shall not be made commercially available in the market during the period of such testing.

   (b) Trial:
      (i) The assignment of spectrum shall be made for trials, undertaken prior to the commercial launch of telecommunication services, for the purpose of demonstration of technology and capability, product stabilisation, ecosystem development, and other similar purposes.
      (ii) The assignee undertaking trial shall ensure that the associated technologies, products, processes or business models undergoing trial, shall not be made commercially available in the market during the period of such trial.
      (iii) On completion of trial, the assignee shall submit a report to the Central Government containing the outcome and creation of any intellectual property rights as a result of such trial.
   (c) Experimentation:

(i) Experimentation means utilisation of radio waves in experiments for the development of science and technology, and for educational purposes.
(ii) The assignment of spectrum in respect of experimentation shall be made for indoor and outdoor environment, in radiating mode, where EIRP is more than 100 mW.
(iii) Experimentation in indoor and outdoor environment, in radiating mode, where EIRP is less than 100 mW, is exempt from the requirement of assignment of spectrum.
(iv) An assignee undertaking experimentation shall ensure that the associated technologies, products, processes or business models undergoing experimentation, shall not be made commercially available in the market during the period of such experimentation.
(v) An assignee undertaking experimentation shall ensure that there shall be no communication between the experimental wireless station in India and such similar station located in any country outside India, without the prior approval of the Central Government in this regard.
(vi) On completion of experimentation, the assignee shall submit a report to the Central Government containing the outcome and creation of any intellectual property rights as a result of such experiment.

(d) Demonstration:
(i) Demonstration includes the technical display, exhibition, proof of concept, evaluation, and demonstration for sale, at specified locations, for a limited duration, without the provision of any telecommunication service or without any generation of revenue.
(ii) The assignment of spectrum in respect of demonstration shall be made for outdoor environment, in radiating mode, where EIRP is more than 100 mW.
(iii) Demonstration in indoor and outdoor environment, in radiating mode, where EIRP is less than 100 mW, is exempt from the requirement of assignment of spectrum.

5. The applicable spectrum charges shall be as specified below:

Particulars	**Spectrum charges for the duration of spectrum assignment letter**
Testing	Rs. 1,000/- per frequency band
Trial	Rs. 1,000/- per frequency band
Experimental	Rs. 1,000/- per frequency band
Demonstration	Rs. 1,000/- per frequency band

Annexure-XIII: Late charges for delayed payment of spectrum charges

1. This annexure shall apply in respect of delayed payment of spectrum charges in respect of the following entries of Schedule I, read with the relevant annexures of Schedule II as specified therein:

S. No.	Entries of Schedule I
1	National security and defence.
2	Law Enforcement and crime prevention.
3	Public broadcasting services.
4	Disaster Management, safeguarding life and property.
5	Promoting scientific research, resource development and exploration.
6	Safety and operation of roads, railways, metro, regional rail, inland waterways, airports, ports, pipelines, shipping, and other transport systems.
7	Conservation of natural resources and wildlife.
8	Meteorological department and weather forecasting.
9	Internationally recognised dedicated bands for amateur stations, navigation, telemetry, and other like usages.
10	Use by Central Government, State Government, or their entities or other authorised entities for safety and operations of mines, ports and oil exploration and such other activities where the use of spectrum is primarily for supporting the safety and operations.
11	Public Mobile Radio Trunking Services, limited to the payment of spectrum fees.
13	Community Radio Stations.
15	Space research and application, launch vehicle operations and ground station for satellite control.
16	Certain satellite-based services such as:
16(a)	Teleports
16(b)	Television channels
16(c)	Direct To Home
16(d)	Headend In The Sky
16(e)	Digital Satellite News Gathering
16(f)(1)	Very Small Aperture Terminal (Captive)
16(g)	National Long Distance
16(h)	International Long Distance
17	Use by Central Government, State Government or their authorised agencies for telecommunication services.

2. Any payment reflected in the account of the Central Government after midnight of the due date for payment, shall be considered as a delay in payment, irrespective of the date on which the payment transaction was initiated by the assignee.

3. In the event of any delayed payment as explained under paragraph 2, the applicable late charges for each Financial Year shall be calculated at the rate of Marginal Cost of Lending Rate (MCLR) of State Bank of India, plus two percent, compounded annually:

Provided that the minimum late charges applicable shall be rupees two hundred and fifty only:

Provided further that a part of the month shall be considered as a full month for the purpose of calculation of late charges.

[F. No. 24-02/2025-UBB]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.06.18 23:48:51 +05'30'